राष्ट्रीय हिंदी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण बुधवार 24 दिसंबर 2025 वर्ष-8,अंक-297 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

हरियाणा में दम घुटने से 5 मजदूरों की मौत

कुरुक्षेत्र में होटल के कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर सोए थे: सभी यूपी के रहने वाले

एजेंसी

कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में यूपी के ठेकेदार सहित 5 मजदूरों की मौत हो गई। पांचों सोमवार को काम से लौटने के बाद जिला जेल के पास होटल के कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर सोए थे। मंगलवार की जब काफी देर तक नहीं उठे तो होटल कर्मचारियों ने पुलिस बुलाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देख सभी के होश उड़ गए। पांचों बेसुध पड़े थे। तुरंत ही सभी को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पांचों शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिए। पुलिस के मुताबिक, सभी मृतक यूपी के सहारनपुर के रहने वाले थे। इनमें चार श्रमिक और एक ठेकेदार था। होटल मैनेजर के मुताबिक, ये पांच सोमवार की शाम को ही इस होटल में आए थे। सभी होटल में पेंट करने के लिए आए थे।फिलहाल, पुलिस सभी के बारे में जानकारी जुटा रही है। होटल के मैनेजर उपेंद्र नैन के मुताबिक, सोमवार शाम को सहारनपुर के शेखपुरा कदीम के रहने वाले ठेकेदार नूर के साथ चार लोग पेंट करने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। शाम को 4:00 बजे के बाद पहुंचे मजदूर रात को खाना खाकर एक कमरे में सो गए थे। बंद कमरे का दरवाजा जब सुबह देर तक नहीं खुला

तो होटल कर्मचारी कंवरपाल ने उसे जानकारी दी। कर्मचारी की सूचना देते ही वे तुरंत मौके पर पहुंचे और दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। मैनेजर के मुताबिक, कमरे का दरवाजा न खुलने पर उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और एक बार फिर खटखटा कर दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। मगर, अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो दरवाजे को तोड़ना पड़ा। दरवाजा टूटते ही अंदर का दृश्य देख सभी के होश उड़ गए। वहां पांच लोग बेहोश पड़े थे। तुरंत ही सभी को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। होटल मैनेजर के मुताबिक, कमरे के अंदर तसला में कोयले जलाए गए थे। प्राथमिक तौर पर इसी कोयले के धुएं के कारण ही पांचों का दम घुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल, पुलिस ने होटल मालिक को बुला लिया है। मृतकों ठेकेदार नूर भी शामिल है। दो मजदूरों की पहचान राजकुमार और रोशन निवासी शेखपुरा कदीम, सहारनपुर, यूपी के रूप में हुई। अन्य दो मजदूरों की अभी पहचान नहीं हुई है, जिनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

राजधानी में सांसों का 'आपातकाल'

■ खतरनाक स्तर पर पहुंचा राजधानी का एक्यूआई

एजेंसी

नई दिल्ली। राजधानी में स्थानीय कारकों के चलते प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में हवा की गति धीमी होने के चलते लगातार सात दिन हवा बेहद खराब श्रेणी में रहने के बाद आज गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। सुबह की शुरूआत धुंध और कोहरे की मोटी परत से हुई। आसमान में स्मॉग की घनी चादर दिखाई दी। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार, मंगलवार सुबह राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 413 दर्ज किया गया है।। यह हवा की बेहद खराब श्रेणी है।। यह हवा की गंभीर श्रेणी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सुबह सात बजे के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी दिल्ली के अलीपुर में एक्यूआई 408, आनंद विहार में एक्यूआई 466, अशोक विहार में 444, आया नगर में 367, बवाना में 427, बुराड़ी में 390, चांदनी चौक इलाके में 425 एक्यूआई दर्ज किया गया है। वहीं, डीटीयू में 420, द्वारका सेक्टर 8 इलाके में 440, आईजीआई एयरपोर्ट टी3 इलाके में 379, आईटीओ में 436, जहांगीरपुरी में 447, लोधी रोड 368, मुंडका 451, नजफगढ़ में 385, पंजाबी बाग में 440, आरकेपुरम 443, रोहिणी 434, सोनिया विहार 413, विवेक विहार 446, वजीरपुर में 440 दर्ज किया गया है।

अफ्रीकी फुटबॉल कोच को दिल्ली बीजेपी पार्षद की धमकी

■ कहा: यहां का पैसा खा रहे हो तो हिंदी सीखो

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली के पटपड़गंज वार्ड से बीजेपी पार्षद रेनू चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे एक अफ्रीकी फुटबॉल कोच को एक महीने के भीतर हिंदी सीखने की चेतावनी देती नजर आ रही हैं। पार्षद कहती हैं कि अगर हिंदी नहीं सीखी तो पार्क छीन लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, यह अफ्रीकी नागरिक करीब 15 साल से उसी इलाके में रह रहा है। उसने दिल्ली नगर निगम से पार्क किराए पर लिया है और इसमें बच्चों को फुटबॉल कोचिंग देता है। पार्षद ने धमकाने का वीडियो खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसमें रेनू चौधरी अफ्रीकन कोच से पूछती हैं कि वह अब तक हिंदी क्यों नहीं सीख पाया? यहां का पैसा खा रहे हो तो हिंदी बोलना सीखो। जब वहां मौजूद कुछ लोग इस बात को मजाक समझकर हंसते हैं, तो पार्षद कहती हैं कि यह कोई मजाक नहीं है और वह इस चेतावनी को लेकर गंभीर हैं।

दिल्ली: वीएचपी का बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन

बांग्लादेशी हिंदू युवक की मौत पर विरोध, यूनुस सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया

एजेंसी

नई दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया। VHP कार्यकर्ता पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। बांग्लादेश में 18 दिसंबर की रात हिंदू युवक दीपू चंद्र की हत्या कर दी गई थी। पहले यह दावा किया जा रहा था कि दीपू ने फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की थी, लेकिन शुरूआती जांच में इसका कोई सबूत नहीं मिला। इस बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया है। यह एक हफ्ते में दूसरी बार है, जब भारतीय उच्चायुक्त को बुलाया गया है। बांग्लादेशी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भारत विरोधी प्रदर्शनों और फिर मैमन सिंह जिले में दीपू की मॉब लिंचिंग को लेकर

दोनों देशों के रिश्ते काफी बिगड़ गए हैं। बांग्लादेश ने मंगलवार को भारत में अपने राजनयिक मिशनों पर हुए हमलों को लेकर गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक इन घटनाओं के विरोध में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया गया। घटनाएं नई दिल्ली और सिलीगुड़ी में हुईं। बांग्लादेश ने कहा कि यह हिंसा और डराने-धमकाने की घटनाएं अस्वीकार्य हैं। ऐसे कृत्य न सिर्फ राजनयिक कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, बल्कि आपसी सम्मान, शांति और सहिष्णुता जैसे मूल्यों को भी कमजोर करते हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, प्रणय वर्मा को भारत में बांग्लादेशी मिशनों की सुरक्षा स्थिति को लेकर बुलाया गया। उन्हें निर्देश दिया गया कि सभी दूतावासों और संबंधित ठिकानों की सुरक्षा कड़ी की जाए। बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि भारत में रहकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार ऐसे बयान दे रही हैं, जिन्हें बांग्लादेश भड़काऊ मानता है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने उच्चायुक्त से कहा कि इन घटनाओं से डिप्लोमैट्स और हाई कमीशन की सुरक्षा पर खतरा पैदा हुआ है। उसने भारत सरकार से अपील की कि वह इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। बयान में यह भी कहा गया कि बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार से इन घटनाओं की जांच कराने, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने और भारत में स्थित बांग्लादेश के राजनयिक मिशनों और उनसे जुड़ी सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। इन घटनाओं में 22 दिसंबर 2025 को सिलीगुड़ी में बांग्लादेश वीजा सेंटर में तोड़फोड़ और 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन शामिल है।

ओडिशा में साल का सबसे बड़ा सामूहिक सरेंडर

■ 22 माओवादियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता

एजेंसी

अनुगुल। ओडिशा के माओवाद प्रभावित मलकानगिरी जिले में मंगलवार को पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले में सक्रिय रहे 22 माओवादियों ने एक साथ आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। यह ओडिशा में वर्ष 2025 का अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक माओवादी आत्मसमर्पण माना जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वालों में एक डिवीजनल कमेटी मेंबर, छह एरिया कमेटी मेंबर और 15 साधारण पार्टी सदस्य शामिल हैं। मलकानगिरी जिला पुलिस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान माओवादियों ने AK–47, आईएनएसएएस, एसएलआर और 303 के तीन राइफल समेत कुल नौ हथियार, भारी मात्रा में गोलाबारूद और विस्फोटक सामग्री पुलिस के हवाले की। बरामद सामग्री में 150 राउंड गोलियां, 13 टिफिन बम, करीब 20 किलो विस्फोटक, जिलेटिन स्टिक, कोडेक्स वायर और माओवादी साहित्य शामिल है। आत्मसमर्पण कार्यक्रम में ओडिशा पुलिस महानिदेशक योगेश बहादुर खुरानिया स्वयं उपस्थित रहे। उन्होंने इसे सुरक्षा बलों की सतत कार्रवाई, सरकार की विकास योजनाओं और पुनर्वास नीति का परिणाम बताया। डीजीपी खुरानिया ने कहा कि सरकार समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले सभी माओवादियों का स्वागत करती है और अन्य भूमिगत माओवादियों से भी हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करने की अपील की।

दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर को पीटने वाले पायलट पर एफआईआर: पुलिस ने हिरासत में लिया

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर से मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने पायलट पर FIR दर्ज कर ली है। आरोपी वीरेंद्र सेजवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। दरअसल 19 दिसंबर को आरोपी ने एक यात्री के साथ मारपीट की थी जिसके बाद पीड़ित ने अपने साथ हुई घटना के कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। घटना के समय आरोपी ऑफ ड्यूटी था। वह उस दिन परिवार के साथ यात्रा कर रहा था। वहीं पैसेंजर अंकित ने दावा किया है कि CT स्कैन में

उसकी नाक की हड्डी में फ्रैक्चर आया है। मारपीट की घटना के बाद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद एअर इंडिया एक्सप्रेस ने भी पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को सस्पेंड कर दिया था। पीड़ित अंकित ने पायलट पर आरोप लगाया था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उसके साथ मारपीट की गई। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कैप्टन वीरेंद्र को लाइन तोड़ने के लिए टोका था। पीड़ित ने कहा था कि उसकी 7 साल की बेटी के सामने उसे पीटा गया। वह अभी भी सदमे में है। अंकित ने कहा कि घटना के बाद उसकी छुट्टियां बर्बाद गईं।

नीरज चोपड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात

एजेंसी

नई दिल्ली। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। नीरज के साथ इस दौरान पत्नी हिमानी मोर भी मौजूद रहीं। नीरज ने इस साल पूर्व टेनिस खिलाड़ी हिमानी से शादी की थी और वह फिलहाल ब्रेक पर चल रहे हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर नीरज के साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने लिखा, 'नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोरी के साथ आज सात, लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। हमने इस दौरान खेल सहित विभिन्न

मुद्दों पर बात की।' भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा इस साल आखिरकार 90 मीटर की बाधा पार करने में सफल रहे, लेकिन वह विश्व चैंपियनशिप में अपने खिताब का बचाव नहीं कर सके थे। नीरज ने दोहा डायमंड लीग में भाला फेंक में मानक माने जाने वाले 90 मीटर की दूरी हासिल की। नीरज ने अपना भाला 90.23 मीटर तक फेंका और ऐसा करने वाले एशिया के तीसरे और कुल मिलाकर 25वें खिलाड़ी बन गए।

दावा : शिवसेना और मनसे मिलकर लड़ेंगे बीएमसी चुनाव

संजय राउत बोले- सीट बंटवारा पूरा, औपचारिक घोषणा बाकी, वोटिंग 15 जनवरी को

एजेंसी

मुम्बई। शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि उद्धव-राज का गठबंधन वास्तव में अस्तित्व में आ चुका है। दोनों दलों के कार्यकर्ता मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में मिलकर काम करने लगे हैं। संजय राउत ने कहा कि सोमवार रात दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे पर अंतिम सहमति बन गई है। संजय का कहना है कि अब केवल गठबंधन की औपचारिक घोषणा बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव-राज के बीच गठबंधन का ऐलान बुधवार दोपहर 12 बजे हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनावों के लिए शिवसेना (UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के बीच दादर, सेवरी, विक्रोली और भांडुप इलाकों में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। यहां दोनों को ही जनता का समर्थन है। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। वोटिंग 15 जनवरी को होनी है। काउंटिंग 16 जनवरी को होगी। न्यूज एजेंसी सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने आगामी पुणे नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के

साथ आने की संभावना पर बात की है। अजित ने रविवार रात कांग्रेस नेता सतेज पाटिल से फोन पर बात की और साथ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा। इस पर पाटिल ने कहा कि वे इस मुद्दे पर पहले अपनी पार्टी के नेताओं से चर्चा करेंगे, इसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। आम आदमी पार्टी (AAP) ने सोमवार को आने वाले बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनावों के लिए अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में पार्टी के नेशनल और स्टेट लीडरशिप के 40 नेता शामिल हैं। अअढ के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, उनके बाद सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और आतिशी हैं। पार्टी ने दुर्गेश पाठक, दिलीप पांडे, सौरभ भारद्वाज, हरपाल सिंह चीमा और इमरान हुसैन जैसे ऑर्गनाइजेशन के अहम चेहरों को भी शामिल किया है। BMC चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं, बल्कि मुंबई की सत्ता, दलों की विश्वसनीयता और आने वाले बड़े चुनावों की दिशा तय करने की लड़ाई है। इसलिए यह महायुति और महाविकास अघाड़ी के लिए साख का सवाल है। 74,000 करोड़ रुपए के बजट वाली एशिया की सबसे बड़ी सिविक बॉडी इटउ पर बिना बंटे शिवसेना ने लगभग दो दशकों तक राज किया था। तब BJP उसकी सहयोगी थी। मुंबई नगर निगम का बजट गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के बजट से भी बड़ा है। यही कारण है कि भाजपा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, कांग्रेस, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। महाराष्ट्र की 288 नगर परिषदों और नगर पंचायत के लिए 2 दिसंबर और 20 दिसंबर को वोटिंग हुई थी।

श्रीनगर से जम्मू तक 80 गांवों में घर-घर तलाशी

घुसपैठ रोकने के लिए कश्मीर पुलिस-सेना का जॉइंट ऑपरेशन, उधमपुर में आतंकी दिखने के बाद एक्शन

एजेंसी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की आशंकाओं के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा कदम उठाया है। सीमा से सटे इलाकों में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए सेना, बीएसएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चला रही है। यह सर्चिंग बॉर्डर एरिया के 80 से ज्यादा गांवों में चलाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, खुफिया इनपुट मिले थे कि आतंकी संगठन घने कोहरे, सर्द मौसम और दुर्गम इलाकों का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर यह बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को मजालता के जंगलों में तब शुरू किया गया जब दो आतंकवादियों के एक घर से खाना लेकर पास के जंगल में भागने की खबर मिली थी। आतंकी शाम करीब 6:30 बजे चोरे मोतु गांव में मंगतु राम के घर गए थे। जम्मू, सांबा, कठुआ और राजौरी जैसे संवेदनशील सीमावर्ती जिलों में जवान घर-घर जाकर तलाशी ले रहे हैं। सांबा के बाबर नाला, पालोरा, त्रेयाल, मनसर और चिल्ला डांगा जैसे इलाकों में तलाशी ली जा रही है। अखनूर

सेक्टर के प्रगवाल और आसपास के गांवों में भी सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। जम्मू जिले में पंसर, मनियारी, पहाड़पुर, तप्पन, मरीड़, तरनाह नाला, बैन नाला और किशनपुर कांडी समेत कई गांवों में तलाशी जारी है। अमीराकदल और महाराजा बाजार के घनी आबादी वाले इलाकों में एक्सप्लोसिव, हथियार, और एम्युनिशन की तलाश के लिए स्निफर डॉग और मेटल डिटेक्टर को लगाया गया। राजौरी के थानामंडी और मंजाकोट में व्यापक अभियान जारी है। एंटी-सैबोटेज चेकिंग और सर्च बख्शी स्टेडियम के पास के इलाकों में की गई, जो कश्मीर में रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की मेन जगह है। लाल चौक का मशहूर क्लॉक टावर, जो पिछले चार सालों में टूरिस्ट हब बन गया है, अमीराकदल से भी थोड़ी ही दूर है, वहां सर्चिंग की गई। पिछले माह बीएसएफ के अधिकारी ने खुलासा किया था कि भारत की ऑपरेशन सिंदूर के बाद नुकसान झेलने के बावजूद पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू क्षेत्र के सामने करीब 72 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय कर दिए हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सशक्त उपभोक्ता ही सशक्त राष्ट्र की नींव

(लेखक -ललित गर्ग)

(राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस - 24 दिसम्बर, 2025)

सरकार द्वारा बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण कानून, मानक निर्धारण संस्थाएँ और शिकायत निवारण तंत्र अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, किंतु उनकी प्रभावशीलता तब ही सिद्ध होगी जब वे कागज़ों से निकलकर ज़मीन पर दिखाई दें। आज आवश्यकता है अधिक सशक्त शासन की, अधिक सक्रिय निगरानी की और अधिक संवेदनशील प्रशासनिक दृष्टि की। उपभोक्ता संरक्षण केवल एक विभाग या मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, यह समग्र शासन व्यवस्था की प्राथमिकता होनी चाहिए।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस केवल एक उपभोक्ताओ से जुड़ी तिथि मात्र नहीं है, बल्कि यह उस मौलिक सत्य की स्मृति है कि किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संतुलन और नैतिक स्वास्थ्य का केंद्र बिंदु उपभोक्ता ही होता है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने परिश्रम की कमाई को भरोसे, आवश्यकता और आशा के साथ बाज़ार में खर्च करता है। किंतु आज यही उपभोक्ता सबसे अधिक ठगा जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है और असुरक्षित महसूस कर रहा है। ठगी, बेईमानी, मिलावट और गुणवत्ता-विहीन उत्पादों ने उपभोक्ता अधिकारों की नींव को हिला दिया है। यह स्थिति केवल आर्थिक शोषण तक सीमित नहीं रही, बल्कि उपभोक्ताओं के मानसिक, शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी जीवन पर गहरे और स्थायी आघात पहुँचा रही है। इसलिये उपभोक्ता दिवस मनाते हुए बाजार को आदर्श एवं स्वस्थ कलेवर देने के साथ उपभोक्ता हितों का संरक्षण जरूरी है।

आज का बाज़ार पहले की तुलना में अधिक जटिल, तेज़ और आक्रामक हो चुका है। उपभोक्ता के सामने विकल्पों की भरमार है, किंतु जानकारी और पारदर्शिता का अभाव है। चमकदार विज्ञापन, आकर्षक पैकेजिंग और भ्रामक दावे उपभोक्ता को निर्णय के उस बिंदु तक ले जाते हैं, जहाँ वह अक्सर वास्तविक गुणवत्ता और सुरक्षा को पहचान ही नहीं पाता। परिणामस्वरूप वह ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने को विवश होता है जो उसके स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुँचाती हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थ, नकली दवाइयाँ, घटिया निर्माण सामग्री और डिजिटल ठगी के नए-नए रूप यह प्रमाणित करते हैं कि उपभोक्ता अधिकारों का हनन अब अपवाद नहीं, बल्कि सामान्य प्रवृत्ति बनता जा रहा है।

यह विडंबना ही है कि जिस दौर में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, उसी दौर में भारतीय उपभोक्ता गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। आर्थिक प्रगति का वास्तविक अर्थ केवल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि नहीं होता, बल्कि यह भी होता है कि उस विकास का लाभ आम नागरिक तक कितनी ईमानदारी और सुरक्षा के साथ पहुँच रहा है। यदि उपभोक्ता को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध नहीं हो पा रहे, तो यह विकास अधूरा और खोखला है। उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन केवल जेब पर चोट नहीं करता, वह राष्ट्र के आत्मविश्वास और नैतिक शक्ति को भी कमजोर करता है।

उपभोक्ता जब बार-बार ठगा जाता है, तो उसके मन में बाज़ार और व्यवस्था दोनों के प्रति अविश्वास जन्म लेता है। यह अविश्वास धीरे-धीरे मानसिक तनाव, चिंता और असुरक्षा की भावना में बदल जाता है। मिलावटी भोजन और नकली दवाइयों से उत्पन्न बीमारियाँ केवल शारीरिक कष्ट नहीं देतीं, बल्कि परिवार और समाज पर दीर्घकालिक आर्थिक बोझ भी डालती हैं। इस प्रकार उपभोक्ता अधिकारों का हनन एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह सामाजिक और राष्ट्रीय समस्या का रूप ले लेता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उपभोक्ता शोषण राष्ट्र की सामूहिक चेतना पर आघात है।

सरकार द्वारा बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण कानून, मानक निर्धारण संस्थाएँ और शिकायत निवारण तंत्र अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, किंतु उनकी प्रभावशीलता तब ही सिद्ध होगी जब वे कागज़ों से निकलकर ज़मीन पर दिखाई दें। आज आवश्यकता है अधिक सशक्त शासन की, अधिक सक्रिय निगरानी की और अधिक संवेदनशील प्रशासनिक दृष्टि की। उपभोक्ता संरक्षण केवल एक विभाग या मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, यह समग्र शासन व्यवस्था की प्राथमिकता होनी चाहिए। जब तक मिलावट, धोखाधड़ी और भ्रामक व्यापारिक प्रथाओं पर त्वरित और कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उपभोक्ता अधिकारों की बात केवल औपचारिक भाषणों तक सीमित रह जाएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि हम उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की ओर देखें, तो स्पष्ट होता है कि वहाँ उपभोक्ता अधिकारों को केवल कानून के रूप में नहीं, बल्कि संस्कृति के रूप में स्वीकार किया गया है। उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा मानक, पारदर्शी जानकारी और त्वरित न्याय वहाँ बाज़ार की अनिवार्य शर्तें हैं। भारत को भी इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए केवल सस्ता उत्पादन पर्याप्त नहीं है, बल्कि उच्च गुणवत्ता और उपभोक्ता संतुष्टि अनिवार्य है। भारतीय उपभोक्ता को यह महसूस होना चाहिए कि वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता से कम सुरक्षित या कम सम्मानित नहीं है।

इस वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम सुरक्षा, गुणवत्ता और विश्वास की बात करती है, जो अपने आप में अत्यंत विचारोत्तेजक है। सुरक्षा केवल उत्पाद की नहीं, बल्कि उपभोक्ता के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा है। गुणवत्ता केवल वस्तु की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की गुणवत्ता है जो उपभोक्ता को न्याय और सम्मान देती है। विश्वास केवल बाज़ार पर नहीं, बल्कि शासन और कानून पर विश्वास है। यदि ये तीनों तत्व सशक्त नहीं होंगे, तो उपभोक्ता दिवस का संदेश अधूरा रह जाएगा। उपभोक्ताओं के हितों की वकालत करता हुआ यह दिवस उपभोक्ताओं के अधिकारों, दायित्वों और संरक्षण की चेतना को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिन याद दिलाता है कि उपभोक्ता केवल खरीददार नहीं, बल्कि बाजार व्यवस्था की आत्मा हैं, बाजार की शक्ति एवं गति है।। बदलते आर्थिक परिवेश में उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना और भी आवश्यक हो गया है। उपभोक्ता संरक्षण कानूनों ने एक मजबूत आधार दिया है, किंतु उनके प्रभावी क्रियान्वयन, त्वरित न्याय और जन-जागरूकता के बिना उपभोक्ता सशक्तिकरण अधूरा रह जाता है। इसलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को औपचारिकता नहीं, बल्कि सतत जनआंदोलन के रूप में देखा जाना चाहिए।

डिजिटल मार्केटिंग की चुनौतियां आज उपभोक्ता हितों के लिए सबसे बड़ी कसौटी बनकर उभरी हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भ्रामक विज्ञापन, फर्जी रिव्यू, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन, छिपी शर्तें और एल्गोरिद्म-आधारित मूल्य भेदभाव उपभोक्ता को असहाय बना रहे हैं। डिजिटल लेनदेन की सुविधा के साथ-साथ साइबर धोखाधड़ी और गलत सूचना का खतरा भी बढ़ा है। ऐसे में उपभोक्ताओं को डिजिटल साक्षर बनाना, प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करना और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना समय की मांग है, ताकि तकनीक उपभोक्ता के लिए सहायक बने, शोषण का साधन नहीं।

'जागो ग्राहक जागो' अभियान को आज क्रांतिकारी रूप देने की आवश्यकता है। यह अभियान केवल नारों और विज्ञापनों तक सीमित न रहकर व्यवहारिक प्रशिक्षण, स्कूल-कॉलेज पाठ्यक्रमों, स्थानीय भाषाओं और डिजिटल माध्यमों से जुड़ना चाहिए। साथ ही उपभोक्ता हितों को लेकर बने कानूनों को अधिक लचीला, सरल और व्यापक पहुंच वाला बनाना जरूरी है, ताकि आम उपभोक्ता बिना भय और जटिलता के न्याय पा सके। त्वरित अदालतें, ऑनलाइन सुनवाई और सामूहिक शिकायतों की प्रभावी व्यवस्था उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करेगी। जब कानून संवेदनशील होंगे और जागरूकता व्यापक, तभी उपभोक्ता सशक्तिकरण वास्तविक अर्थों में संभव होगा। आज आवश्यकता है कि उपभोक्ता अधिकारों को राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बनाया जाए। उपभोक्ता को जागरूक करना, उसे उसके अधिकारों और दायित्वों की जानकारी देना और उसे यह विश्वास दिलाना कि व्यवस्था उसके साथ खड़ी है, यह शासन की नैतिक जिम्मेदारी है। साथ ही व्यापार जगत को यह समझना होगा कि अल्पकालिक लाभ के लिए उपभोक्ता के साथ किया गया अन्याय दीर्घकाल में स्वयं उनके अस्तित्व को भी संकट में डाल सकता है। एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था वही होती है जिसमें उपभोक्ता और उत्पादक के बीच भरोसे का संबंध हो।

अंततः यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। उपभोक्ता का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है और उपभोक्ता की सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा है। जब भारत विकास की नई ऊँचाइयों की ओर बढ़ रहा है, तब यह अनिवार्य है कि यह विकास उपभोक्ता के स्वास्थ्य, मानसिक शांति और विश्वास की कीमत पर न हो। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हमें यही संदेश देता है कि सशक्त उपभोक्ता ही सशक्त राष्ट्र की नींव रख सकता है और इस नींव को मजबूत करने के लिए शासन, समाज और बाज़ार सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी होगी। इसी से नया भारत, सशक्त भारत एवं समृद्ध भारत बन सकेगा।

संपादकीय

सड़क व्यवहार के प्रति जागरूक

लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का वह बयान तार्किक ही है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं मानवीय व्यवहार से जुड़ी हैं। निश्चय ही यदि वाहन चालकों को सड़क व्यवहार के प्रति जागरूक किया जाए और हम जिम्मेदारी-सावधानी से वाहन चलाएं तो हर साल हजारों जिंदगियां बचायी जा सकती हैं। भारत में दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले कम वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं, लेकिन सड़क हादसों के मामले में हम अव्वल हैं। विडंबना देखिए कि एक साल में देश के भीतर करीब पांच लाख सड़क हादसे दर्ज किए जाते हैं। बड़ी संख्या उन हादसों की भी है जो छोटे शहरों व भीतरी इलाकों में होते तो हैं, लेकिन दर्ज नहीं होते। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश में हर साल करीब 1.8 लाख लोग इन हादसों में मारे जाते हैं। लाखों लोग इन हादसों में घायल होते हैं। हजारों लोग ऐसे भी होते हैं जो हादसों के बाद जीवनपर्यंत सामान्य जीवन नहीं जी पाते हैं। दुखद स्थिति यह भी है कि मरने वालों में सर्वाधिक संख्या युवाओं की होती है। एक आंकड़े के अनुसार मरने वालों में 66 फीसदी लोग 18 से 34 साल के बीच होते हैं। जो अपने परिवार के कमाने वाले व्यक्ति होते हैं। फलत- हादसे के बाद कई परिवार गरीबी के दलदल में धंस जाते हैं। दरअसल, सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण तेज गति से वाहन चलाना भी है। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि ओवर स्पीडिंग से 68 फीसदी से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। वहीं निर्धारित स्पीड से अधिक तेजी से वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं के चलते ही 68 फीसदी मौतें भी होती हैं। निश्चित रूप से ये हादसे व मौतें मानवीय व्यवहार की कमजोरी से जुड़े हैं। जहां देश में राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे का तेजी से विस्तार हुआ है तो बेहतर सड़कों में वाहन चालकों की गति अनियंत्रित हो चली है। जो कालांतर सड़क हादसों की वजह बनती है। यह विडंबना है कि हम अकसर सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हैं। आज की युवा पीढ़ी हेलमेट पहनने से परहेज करती है। यह जानते हुए कि हादसों में सिर की चोट जानलेवा बन जाती है। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में हेलमेट न लगाने के कारण 54,568 लोगों की मौत हुई। वहीं सीट बेल्ट न लगाने से 16 हजार से अधिक यात्रियों की जान गई। इन हादसों की एक बड़ी वजह ऐसे अकुशल चालकों का होना भी था, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। आंकड़ों के अनुसार दुर्घटनाओं के लिये जिम्मेदार चालकों में 33,827 ऐसे थे जिनके पास लाइसेंस नहीं थे। देश में बड़ी संख्या ऐसे चालकों की होती है, जो मेडिकली फिट नहीं होते। इसके अलावा जुगाड़ से ले-देकर लाइसेंस बनाने वालों की भी कमी नहीं है। वे वाहन चलाने की पर्याप्त योग्यता व अनुभव के बिना ही चालक बन बैठते हैं। हाल के वर्षों में नशे की हालात में वाहन चलाने का फैशन भी बना है। कई हादसों के बाद खुलासा हुआ कि फलां चालक नशे में धुत था। हालांकि, महानगरों व शहरों में नाका लगाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की पकड़-धकड़ की जाती है। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे पर ऐसी जांच बड़े पैमाने पर होती नजर नहीं आती। वहीं ऐसे चालकों की भी कमी नहीं है, जो फोन पर बात करते हुए वाहन चलाते हैं।

उपभोक्ता जागरूकता से समृद्ध समाज की ओर

(लेखक- योगेश कुमार गोयल)

- जागरूक होंगे, तभी मिलेगा इंसाफ

(राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (24 दिसम्बर) पर विशेष)

उपभोक्ताओं के विभिन्न हितों और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए देश में प्रतिवर्ष 24 दिसम्बर को 'राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस' मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनके हितों के लिए बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमों तथा उनके अंतर्गत आने वाले कानूनों की जानकारी देना है। दरअसल ऑनलाइन खरीददारी हो या ऑफलाइन, ग्राहकों को कई बार सामान की गड़बड़ी अथवा अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसी तरह की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाने तथा उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। हालांकि वर्ष 2020 तक विभिन्न ई-कॉमर्स साइटों से ऑनलाइन खरीददारी को लेकर उपभोक्ताओं को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं था लेकिन उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 (कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) में ई-कॉमर्स को भी दायरे में लाकर उपभोक्ताओं को और मजबूती देने का प्रयास किया गया। पुराना उपभोक्ता संरक्षण कानून करीब साढ़े तीन दशक पुराना हो चुका था, जिसमें समय के साथ बड़े बदलावों की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसीलिए ग्राहकों के साथ अक्सर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों को ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए 20 जुलाई 2020 को 'उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019' (कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) लागू किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की ठगी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए कई प्रावधान शामिल हैं।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस वास्तव में उपभोक्ताओं को उनकी शक्तियों और अधिकारों के बारे में जागरूक करने का महत्वपूर्व अवसर है। भारत में उपभोक्ता आन्दोलन की शुरूआत मुम्बई में वर्ष 1966 में हुई थी। तत्पश्चात् पुणे में वर्ष 1974 में ग्राहक पंचायत की स्थापना के बाद कई राज्यों में उपभोक्ता कल्याण के लिए संस्थाओं का गठन किया गया। इस प्रकार उपभोक्ता हितों के संरक्षण की दिशा में यह आन्दोलन आगे बढ़ता गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर 9 दिसम्बर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बार 24 दिसम्बर 1986 को देशभर में लागू किया गया। पिछले कई वर्षों से भारत में प्रतिवर्ष इसी दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस मनाए जाने का मूल उद्देश्य यही है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और अगर वे धोखाधड़ी, कालाबाजारी, घटतौली इत्यादि के शिकार होते हैं तो वे इसकी शिकायत उपभोक्ता अदालत में कर सकें।

उपभोक्ता संरक्षण कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक वह व्यक्ति उपभोक्ता है, जिसने किसी वस्तु या सेवा के क्रय के बदले धन का भुगतान किया है या भुगतान करने का आश्वासन दिया है और ऐसे में किसी भी प्रकार के शोषण अथवा उत्पीड़न के खिलाफ वह अपनी आवाज उठा सकता है तथा क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। खरीदी गई किसी वस्तु, उत्पाद अथवा सेवा में कमी या उसके कारण होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के बदले उपभोक्ताओं को मिला कानूनी संरक्षण ही उपभोक्ता अधिकार है। यदि खरीदी गई किसी वस्तु या सेवा में कोई कमी है या उससे आपको कोई नुकसान हुआ है तो आप उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने उपभोक्ताओं को छह प्रमुख अधिकार प्रदान किए हैं, जिनमें सुरक्षा का अधिकार के तहत खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से बचाव का अधिकार, सूचना का अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और कीमत की सही जानकारी का अधिकार, विकल्प का अधिकार के तहत प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं का चयन का अधिकार, सुने जाने का अधिकार के तहत उपभोक्ता की शिकायतों और समस्याओं पर ध्यान दिया जाना का अधिकार, निवारण का अधिकार के तहत उपभोक्ता की शिकायतों और समस्याओं पर ध्यान दिया जाना का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के खिलाफ न्याय का अधिकार शामिल हैं। जहां तक उपभोक्ता की जिम्मेदारियां की बात है तो उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे खरीदारी से पहले उत्पाद की गुणवत्ता और वैधता की जांच करें, नकली और घटिया उत्पादों से बचने के लिए प्रमाणित ब्रांड्स को ही प्राथमिकता दें, अपनी शिकायतों को दर्ज कराने में सक्रिय रहें, जागरूकता फैलाने में योगदान दें।

अगर उपभोक्ताओं का शोषण होने और ऐसे मामलों में उनके द्वारा उपभोक्ता अदालत की शरण लिए जाने के बाद मिले न्याय के कुछ मामलों पर नजर डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता अदालतों का उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में क्या योगदान है। दरअसल विभिन्न छोटी-बड़ी समस्याओं का सामना जीवन में कभी न कभी हम सभी को करना पड़ता है लेकिन अधिकांश लोग अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ते। इसका प्रमुख कारण यही है कि देश की बहुत बड़ी आबादी अशिक्षित है, जो अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति अनभिज्ञ है। हालांकि जब शिक्षित लोग भी अपने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति उदासीन नजर आते हैं तो हैरानी होती है। यदि आप एक उपभोक्ता हैं और किसी भी प्रकार के शोषण के शिकार हुए हैं तो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़कर न्याय पा सकते हैं। कोई वस्तु अथवा सेवा लेते समय हम धन का भुगतान तो करते हैं पर बदले में उसकी रसीद नहीं लेते। शोषण से मुक्ति पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप जो भी वस्तु, सेवा अथवा उत्पाद खरीदें, उसकी रसीद अवश्य लें। यदि आपके पास रसीद के तौर पर कोई सबूत ही नहीं है तो आप अपने मामले की पैरवी सही ढ़ंग से नहीं कर पाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे अनेक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें उपभोक्ता अदालतों से उपभोक्ताओं को पूरा न्याय मिला है लेकिन आपसे यह अपेक्षा तो होती ही है कि आप अपनी बात अथवा दावे के समर्थन में पर्याप्त सबूत तो पेश करें। उपभोक्ता अदालतों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनमें लंबी-चौड़ी अदालती कार्रवाई में पड़े बिना ही आसानी से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यही नहीं, उपभोक्ता अदालतों से न्याय पाने के लिए न तो किसी प्रकार के अदालती शुल्क की आवश्यकता पड़ती है और मामलों का निपटारा भी शीघ्र होता है।

(लेखक साढ़े तीन दशक से पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार हैं)

धर्म की शरण

हर संसारी प्राणी अपनी सुरक्षा के लिए शरण की खोज करता है। प्राणी उपयुक्त शरण मिलने पर उसे स्वीकार भी कर लेता है। बहिर्दर्शी व्यक्ति अपने पारिवारिक जनों को शरण मानता है। परिवार के लोग किसी सक्षम सदस्य को शरण मानते हैं। किंतु वे तुम्हें त्राण और शरण देने में समर्थ नहीं हैं और तुम उनको त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं हो। यह आगम-वाणी मनुष्य को अपनी सही स्थिति का बोध देती है। वह जब चारों ओर से अत्राण और अशरण होकर असहाय हो जाता है, उस समय उसकी अंतमरुखी चेतना में चार प्रकार की शरण आविर्भूत होती है- अर्हत्, सिद्ध, साधु और धर्म। ये चार तत्व ऐसे हैं, जो व्यक्ति को शात शरण दे सकते हैं। इन चारों शरणों में तीन तत्व किसी अपेक्षा से परे भी हो सकते हैं किंतु चौथा तत्व धर्म अपना निजी ही है। इसकी शरण में जाने के लिए कोई अपेक्षा नहीं केवल अपनी वृत्तियों को मोड़ने की जरूरत है।

धर्म क्या है? जो सबको समता और शांति का पाठ पढ़ाए, वह धर्म है। जिस धर्म के सहारे सुख-सुविधा के साधन जुटाए जाते हैं, प्रतिष्ठा की कृत्रिम भूख को शांत किया जाता है, प्रदर्शन और आडंबर को प्रोत्साहन दिया जाता है, उस धर्म की शरण स्वीकार करने से शांति नहीं मिल सकती। ऐसा धर्म समता का सूत्र नहीं दे सकता।

धर्म की व्याख्या में अब तक हजारों ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, पर उनसे धर्म का सही रूप परिभाषित नहीं हो सका। क्योंकि अधिक व्याख्याकारों ने अपनी धारणा के परिवेश में उसे व्याख्यायित किया है। मेरे अभिमत से धर्म का अर्थ है स्वभाव।

स्वभाव को उपलब्ध करने के लिए उसमें रमण करने की जरूरत है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में रमण कर लेता है, वह धर्म की शरण पा लेता है। उसे अपनी शरण उपलब्ध हो जाती है।

धर्म या स्वभाव- रमण का एक सूत्र है- पदार्थ प्रतिबद्धता का अभाव। कोई व्यक्ति अभाव या अतिभाव के कारण पदार्थ से प्रतिबद्ध नहीं होता है, यह वास्तव में धर्म नहीं है। अभाव में जो व्यक्ति संग्रह नहीं करता, वह त्यागी नहीं होता। इसी प्रकार अतिभाव में पदार्थ का विसर्जन करने वाला भी त्यागी नहीं हो सकता।

विचार मंथन

शेख हसीना के कारण भारत- बांग्लादेश संबंधों में दरार?

(लेखक-सनत जैन)

- सांप्रदायिक हिंसा बनी दोनों देशों के लिए चुनौती

भारत और बांग्लादेश के संबंध 50 वर्ष तक के लंबे समय में आपसी विश्वास, सहयोग और साझा इतिहास की मजबूत बुनियाद पर टिके रहे। शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश ने भारत के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग, सीमा प्रबंधन और आर्थिक साझेदारी को प्राथमिकता दी। हाल के वर्षों में कुछ घटनाक्रमों और दोनों देशों के नीतिगत फैसलों मे भ्रष्टाचार को लेकर दोनों देशों के संबंधों में तनाव और दूरियों को पैदा किया है। जिसका असर दोनों देशों के सामाजिक एवं धार्मिक ताने-बाने पर भी दिखने लगा है। सबसे पहले राजनीतिक स्तर पर देखें, तो शेख हसीना सरकार पर यह आरोप लगा, कि उन्होंने चुनाव में धोखाधड़ी और आंतरिक राजनीति में कठोर रुख अपनाया। उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार बड़ी तेजी के साथ बढ़ा। आम जनता की असहमति की आवाज़ों को बर्बरता के साथ दबाया गया। इससे बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में असंतोष बढ़ा। जब किसी देश में आंतरिक अस्थिरता विद्रोह के रूप में बढ़ती है तो उसका सीधा असर उस देश के साथ ही साथ पड़ोसी देशों के रिश्तों पर भी पड़ने लगता है। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ बगावत हुई, उन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। भारत सरकार ने शेख हसीना को शरण दी। उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंध बिगड़ना शुरू हो गए। धार्मिक आधार पर वैमनष्यता फैलाई गई और फिर गंदी राजनीति शुरू हो गई। जिसने दो देशों के वर्तमान संबंधों पर आग में घी डालने का काम किया। भारत के साथ कुछ मुद्दों— जैसे तीस्ता जल समझौता, सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं और व्यापार असंतुलन को लेकर दूरियां बनना शुरू हो गई। अदानी के बिजली घर को लेकर भी भ्रष्टाचार और महंगी बिजली को लेकर बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एक वातावरण बनना शुरू हुआ। जिससे दोनों देशों के नागरिकों और राजनेताओं के बीच में अविश्वास की भावना बढ़ती चली गई। जो अब दुश्मनी के रूप में देखने को मिल रही है। वर्तमान में जिस तरह की सांप्रदायिक हिंसा दोनों देशों में देखने को मिल रही है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश के हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़, हिंदुओं के घरों पर हमले और जबरन बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाने की घटनाओं ने भारत में चिंता पैदा कर दी है। हद यह है कि बांग्लादेश मे हो रही घटनाओं की प्रतिक्रिया भारत में भी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर तीखी बयानबाज़ी के साथ बांग्लादेश विरोध देखने को मिल रहा है। भारत स्थित बांग्लादेशी दूतावास के समक्ष प्रदर्शन हो रहा है। उससे दोनों देशों के बीच में संबंध और भी बिगड़ते हुए दिख रहे हैं।

इन तमाम घटनाओं को लेकर अब भारत में मुस्लिम समुदाय में डर, भय और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। दोनों देशों में हिंदू और मुस्लिम वर्ग के बीच अविश्वास बढ़ा है। जो किसी भी सूरत में दोनों देशों के लिए शुभ संकेत नहीं हैं। मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका भी इस मामले में कम जिम्मेदार नहीं है। भ्रामक सूचनाओं और आधी-अधूरी खबरों तथा एक दूसरे के खिलाफ उत्तेजक बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया है। सीमापार की घटनाओं को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, जिससे सामाजिक एवं धार्मिक वेमनष्यता आम नागरिकों के बीच नफरत और भय फैलाने का कारण बन रहा है। बांग्लादेश और भारत के बीच का एक सच यह भी है। भारत और बांग्लादेश की जनता के बीच सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक रिश्ते बेहद गहरे हैं। शेख हसीना के कारण पैदा हुए तनाव को स्थायी मान लेना, दोनों देशों के लिए ठीक नहीं होगा। जरूरत इस बात की है, कि दोनों देश संयम के साथ संवाद और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ें। बांग्लादेश को अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। वहीं भारत को भी प्रतिक्रिया में संतुलित और जिम्मेदारी भरा रुख अपनाना चाहिए। भारत-बांग्लादेश के बीच में जो संबंध बिगड़े हैं उसके पीछे शेख हसीना को भारत में शरण दिया जाना मुख्य कारण है। किसी एक नेता के कारण दोनों देशों की करोड़ों जनता को कष्ट में नहीं डाला जा सकता है। दोनों देशों को सांप्रदायिक सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हुए इस मामले का तुरंत निपटारा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान तनाव को किस तरह एक बेहतर अवसर के रूप में बदला जा सकता है, जिसके कारण भारतीय उप महाद्वीप में शांति व स्थिरता का मार्ग प्रशस्त हो। भारत सरकार को बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति और शेख हसीना को लेकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करना होगा।

बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए शेख हसीना को भारत के स्थान पर अन्य किसी राष्ट्र में शरण लेनी चाहिए। ताकि भारत और बांग्लादेश में शांति स्थापित हो सके। दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते थे, वह कायम रह सकें। यही वर्तमान समय की मांग है। भारत सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। वह इस मामले में गंभीरता के साथ विचार करते हुए किस तरह से दूरगामी रिश्ते बेहतर किये जा सकते हैं। इसके लिए कोई बीच का रास्ता समझौते के तौर पर निकालना होगा। इसकी पहल भारत को ही करनी होगी।

सोना-चांदी के बाद अब तांबा बनेगा निवेशकों की नई पसंद

- एआई डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी बढ़ा रहे तांबे की मांग

नई दिल्ली । साल 2025 में सोना और चांदी ने निवेशकों को हैरान करने वाला रिटर्न दिया, लेकिन अब तांबा निवेशकों की नजर में नया किंग बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में तांबे की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बाजार विशेषज्ञों के मुतो बिक एआई डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी), ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिफिकेशन की बढ़ती जरूरत तांबे की मांग को तेजी से बढ़ा रही है। वैश्विक तांबा बाजार में 2025 में लगभग 1.24 लाख टन और 2026 में 1.50 लाख टन की कमी रहने का अनुमान है। भारत में तांबे का एकमात्र प्रमुख उत्पादक हिंदुस्तान कॉपर है, जिससे सप्लाई सीमित बनी हुई है। उनका कहना है कि बिजली के इस्तेमाल में वृद्धि, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और ग्रिड वायरिंग में तांबे की अहम भूमिका इसे रणनीतिक धातु बनाती है। इस साल अब तक तांबे की कीमतों में लगभग 35 फीसदी की तेजी आई है, जो 2009 के बाद सबसे बड़ी बढ़त मानी जा रही है। वर्तमान में तांबे की कीमत लगभग 12,000 डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक पहुँच चुकी है। निवेशक इसे सिर्फ सट्टा नहीं मान रहे, बल्कि वास्तविक मांग पर आधारित निवेश विकल्प के रूप में देख रहे हैं। बताया जा रहा है` कि 2026 में वैश्विक तांबे की मांग 27 मिलियन टन तक पहुंच सकती है, जिसमें अकेले चीन की मांग में 3.7 फीसदी की वृद्धि शामिल है। विशेषज्ञ मानते हैं कि एआई डेटा सेंटर्स, इले क्ट्रिक वाहनों और ग्रीन एनर्जी की तेजी से बढ़ती जरूरत तांबे की कीमतों को नए रिकॉर्ड तक ले जा सकती है।

आरआईटीईएस को दक्षिण अफ्रीका में 315 करोड़ का लोकोमोटिव ठेका

- भारत की रेल तकनीक का अंतरराष्ट्रीय विस्तार, डेढ़ साल में प्रोजेक्ट पूरा

नई दिल्ली । रेल अवसंरचना, परामर्श एवं इंजीनियरिंग कंपनी (आरआईटीईएस लिमिटेड) ने दक्षिण अफ्रीका की नडालामा कैपिटल लिमिटेड से डीजल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की आपूर्ति और संचालन का ठेका हासिल किया है। ठेके की कुल लागत 315.7 करोड़ रुपये (35.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है। कंपनी ने बीएसई को बताया कि यह प्रोजेक्ट डेढ़ वर्ष में पूरा किया जाएगा। आरआईटीईएस लिमिटेड, जो रेल मंत्रालय के अधीन नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, इस ठेके के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रही है। इस परियोजना से भारत-दक्षिण अफ्रीका के द्विपक्षीय रेल सहयोग को भी बल मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, यह ठेका भारतीय रेल प्रौद्योगिकी की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक है।

उत्सर्जन धोखाधड़ी मामले में मर्सिडीज-बेंज 14.96 करोड़ डॉलर भुगतान करेगी

मैडिसन । मर्सिडीज-बेंज यूएसए और उसकी मूल कंपनी डेमलर एजी ने उत्सर्जन धोखाधड़ी के आरोपों के निपटान के लिए 14.96 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई है। अटॉर्नी जनरल के एक गठबंधन ने यह घोषणा की। 008 से 2016 के बीच, जर्मनी की कंपनी ने 211,000 से अधिक डीज़ल कारों और वैनों में ऐसा सॉफ़्टवेयर लगाया, जो परीक्षण के समय उत्सर्जन नियंत्रण को बेहतर दिखाता था, लेकिन सामान्य संचालन में यह नियंत्रण कम कर देता था। मझौते के तहत मर्सिडीज को रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करना होगा और किसी भी प्रकार की भ्रामक बिक्री या विपणन से बचना होगा। 2020 में कंपनी ने अमेरिकी सरकार और कैलिफ़ोर्निया राज्य को पहले ही 1.5 अरब डॉलर का भुगतान किया था। इसी तरह वोल्क्सवेगन को पहले उत्सर्जन धोखाधड़ी के मामलों में 2.8 अरब डॉलर का भुगतान करना पड़ा था।

आरबीआई ने अक्टूबर में रुपए को गिरने से बचाने 11.9 अरब डॉलर बेचे

- डॉलर की खरीद 2.2 अरब डॉलर से बढ़कर 17.7 अरब डॉलर हुई

मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अक्टूबर 2025 में रुपये की स्थिरता बनाए रखने के लिए स्पॉट मार्केट में 11.9 अरब डॉलर की शुद्ध बिक्री की। सितंबर में यह राशि 7.9 अरब डॉलर थी। इस दौरान डॉलर की खरीद 2.2 अरब डॉलर से बढ़कर 17.7 अरब डॉलर हो गई, जबकि बिक्री 192 फीसदी बढ़कर 29.6 अरब डॉलर हो गई। इसका मुख्य उद्देश्य रुपये को गिरने से रोकना था। आरबीआई ने भविष्य की कीमतों पर नियंत्रण के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का भी उपयोग किया। अक्टूबर में शुद्ध फॉरवर्ड बिक्री 63.6 अरब डॉलर तक बढ़ी, जो सितंबर में 59.4 अरब डॉलर थी। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर तत्काल दबाव कम हुआ और निवेशकों को यह भरोसा मिला कि जरूरत पड़ने पर डॉलर उपलब्ध होंगे। एक्सचेंज-ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ) बाजार में आरबीआई ने शुद्ध पोजीशन न्यूट्रल रखी।

अक्टूबर में खरीदी और बिक्री दोनों 2.3 अरब डॉलर रही, जबकि ट्रेडिंग वॉल्यूम 73.5 फीसदी बढ़ा। शुद्ध फ्यूचर्स बिक्री अक्टूबर में घटकर 1.4 अरब डॉलर रह गई। आंकड़ों से पता चलता है कि आरबीआई ने रुपए को लगभग 88-89 प्रति डॉलर के स्तर से नीचे गिरने से रोकने पर ध्यान केंद्रित किया। अक्टूबर में प्रभावी हस्तक्षेप मूल्य 88.25 रुपए प्रति डॉलर रहा, जो सितंबर के 88.35 रुपए से थोड़ा कम था।

रुपया बढ़त पर बंद

मुंबई । अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मंगलवार को रुपया 13 पैसे की बढ़त पर बंद हुआ। सुबह शुरुआती कारोबार में रुपये में कमजोरी देखी गई। घरेलू शेयर बाजारों में नरमी और विदेशी निवेशकों की पूंजी निकासी के चलते रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे गिरकर 89.73 पर आ गया। इससे पहले सोमवार को रुपया 89.68 पर बंद हुआ था। हालांकि, डॉलर में कमजोरी और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने स्थानीय मुद्रा को निचले स्तर पर कुछ समर्थन दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया शुरुआती स्तर 89.67 पर खुला था, लेकिन बाद में गिरकर 89.73 पर आ गया। छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.20 फीसदी की गिरावट के साथ 98.08 पर रहा, जिससे रुपये को स्थिरता मिली।

अमेरिका में बनी कारों को घरेलू बाजार में बेचेगी टोयोटा

नई दिल्ली ।

जापानीज कंपनी टोयोटा साल 2026 से अमेरिका में बनी कुछ कारों को घरेलू बाजार में बेचेगी। टोयोटा के मुताबिक, अमेरिका में बने कैमरी सेडान, हाईलैंडर एसयूवी और टुंड्रा पिक-अप ट्रक को जापान में बिक्री के लिए पेश किया जाएगा। ये वाहन अमेरिका के केंटकी, इंडियाना और टेक्सास स्थित प्लांट्स में तैयार किए जाते हैं। कंपनी का कहना है कि इससे वह जापानी ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा कर सकेगी और साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग भी बढ़ेगा। दरअसल, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में जापान से अमेरिका आने वाली कारों और ऑटो पार्ट्स पर भारी टैरिफ लगाए गए थे। इससे जापानी ऑटो कंपनियों पर काफी दबाव बढ़ गया था। टोयोटा का यह फैसला उसी पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है, जहां कंपनी अमेरिका के प्रति 'गुडविल' दिखाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के ऑटो एनालिस्ट तात्सुओ योशिदा के अनुसार, कैमरी और हाईलैंडर जैसी गाड़ियां जापानी सड़कों और पार्किंग स्पेस के हिसाब से काफी बड़ी हैं। इसके अलावा, लेफ्ट-हैंड ड्राइव भी जापानी ग्राहकों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। अगर भविष्य में राइट-हैंड ड्राइव वर्जन पेश किए जाते हैं, तो मांग बढ़ने की संभावना बन सकती है। बता दें कि टोयोटा कंपनी के इस कदम को सिर्फ बिजनेस रणनीति नहीं, बल्कि अमेरिका-जापान के बीच ट्रेड रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

शेयर बाजार में मिला-जुला कारोबार हुआ

सेंसेक्स 42.64 अंक गिरा, निफ्टी 4.75 अंक ऊपर आया

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को मिला-जुला रुख रहा। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार सपाट बंद हुआ। एशियाई बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के बाद भी बिकवाली हावी होने से दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 42.64 अंक टूटकर 85,524.84 और 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 4.75 अंक ऊपर आकर 26,177.15 पर बंद हुआ था। आज कारोबार के दौरान केवल एफएमसीजी, मेटल और उर्जा शेयरों में ही तेजी रही। निफ्टी मेटल और उर्जा शेयरों में बढ़त रही। वहीं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी ऑटो में भी हल्की तेजी रही जबकि निफ्टी आईटी , निफ्टी पीएसयू बैंक 0, निफ्टी फार्मा और निफ्टी रियल्टी में गिरावट रही।

सेंसेक्स के शेयरों की बात करें तो टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोटक महिंद्रा बैंक, एचसीएल टेक, एचयूएल, बजाज फाइनेंस, एमएंडएम के शेयरों में तेजी रही। वहीं भारती एयरटेल, सन फार्मा, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, ट्रेंट, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में गिरावट रही।

आज साप्ताहिक एक्सपायरी पर निफ्टी ने एक सीमित दायरे में कारोबार किया। बाजार सपाट बंद हुआ पर व्यापक स्तर पर बाजार में तेजी थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 2,292 शेयरों में तेज जबकि 1,892 शेयरों में गिरावट रही। 181 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ।

इससे पहले आज सुबह भारतीय बाजारों की शुरुआत सपाट स्तर पर रही। ,सुबह शुरुआत के बाद निफ्टी 50 7.5 अंक की मामूली गिरावट के साथ 26,164.20 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। वहीं सेंसेक्स 50.96 अंक फिसलकर 85,516.52 पर आ गया। बाजार में सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। आज एशियन पेंट्स, एटरनल और भारती एयरटेल के शेयर भी नुकसान में रहे। वहीं एशियाई बाजारों में भी तेजी देखने को मिली। जापान का निक्कई 225 लगभग स्थिर रहा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.73 फीसदी और ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी एसएएक्स 200 0.42 फीसदी ऊपर कारोबार करता दिखा। अमेरिकी बाजारों में भी हॉलिडे शॉर्टेंड वीक में सकारात्मक रुख रहा। एसएंडपी 500 0.64 फीसदी, नेस्डेक कम्पो जिट 0.52 फीसदी और डाओ जोंस 0.47 फीसदी बढ़े।

नवंबर में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि घटकर 1.8 प्रतिशत पर

- पिछले साल नवंबर महीने में 5.8 प्रतिशत थी

नई दिल्ली । देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि नवंबर 2025 में घटकर 1.8 प्रतिशत रह गई, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 5.8 प्रतिशत थी। कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और बिजली के उत्पादन में कमजोरी इसके मुख्य कारण रहे। अक्टूबर में इन उद्योगों का उत्पादन 0.1 प्रतिशत घटा था। अप्रैल-नवंबर 2025-26 में आठ प्रमुख उद्योगों का कुल उत्पादन 2.4 प्रतिशत बढ़ा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में वृद्धि 4.4 प्रतिशत थी। इससे पता चलता है कि इस वर्ष उद्योगों की वृद्धि पिछली अवधि की तुलना में धीमी रही। नवंबर में कोयला और इस्पात उत्पादन में नरमी आई। वहीं उर्वरक और सीमेंट उत्पादन ने बेहतर प्रदर्शन किया, क्रमशः 5.6 प्रतिशत और 14.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। मासिक आधार पर आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर से नवंबर के बीच अधिकांश क्षेत्रों में सुधार हुआ। एक अर्थशास्त्री के अनुसार त्योहारों के बाद नवंबर में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि सुधरी, लेकिन यह अभी भी सुस्त है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक नवंबर में 3.5-4.5 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है।

सिप्ला ने भारत में लॉन्च की पहली इनहेल्ड इंसुलिन 'अफ्रेजा'

- डायबिटीज पीड़ित वयस्कों के लिए इंजेक्शन का नया विकल्प, सांस के जरिए ली जाने वाली इंसुलिन

नई दिल्ली ।

दवा कंपनी सिप्ला ने भारत में डायबिटीज से पीड़ित वयस्कों के लिए इनहेल्ड इंसुलिन 'अफ्रेजा' को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके साथ ही अफ्रेजा भारत में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होने वाली पहली ऐसी इंसुलिन बन गई है, जिसे इंजेक्शन की बजाय सांस के जरिए लिया जाता है। कंपनी के अनुसार उसे पिछले साल के अंत में इस दवा के विशेष वितरण और विपणन के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) से नियामकीय मंजूरी मिली थी। अफ्रेजा एक तेजी से असर करने वाली इंसुलिन है, जिसे मुंह से सांस के जरिए लिया जाता है। इसका निर्माण अमेरिका की मैनकाइंड कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है। यह दवा एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले कार्ट्रिज में उपलब्ध होती है, जिसे एक छोटे, हाथ में पकड़े जाने वाले इनहेलर उपकरण के माध्यम से लिया जाता है। कंपनी के मुताबिक, इंसुलिन लेने के बाद यह तेजी से घुल जाती है और लगभग 12 मिनट के भीतर ब्लड ग्लूकोज को कम करना शुरू कर देती है। इस उपचार की शुरुआत आमतौर पर दिन के प्रमुख भोजन के साथ की जाती है और मरीज की क्लीनिकल जरूरतों के अनुसार इसकी खुराक को समायोजित किया जा सकता है। सिप्ला ने बताया कि यह इनहेल्ड फॉर्मूलेशन टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित वयस्कों के लिए इंजेक्टेबल प्रैंडियल इंसुलिन का एक वैकल्पिक विकल्प है। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि इंजेक्शन से जुड़ी चिंता, इलाज की जटिलता और व्यवहार संबंधी कारणों के चलते कई मरीज इंसुलिन थेरेपी शुरू करने में देरी करते हैं या बीच में छोड़ देते हैं।

विदेश भेजे जाने वाले धन में सालाना आधार पर 1.81 प्रतिशत की गिरावट

यात्रा और शिक्षा खर्च घटे, लेकिन विदेशी निवेश में तेज उछाल

नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की उदारीकृत धनप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत अक्टूबर 2025 में विदेश भेजे जाने वाले धन में सालाना आधार पर 1.81 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार यह धनप्रेषण एक साल पहले के 2.40 अरब डॉलर की तुलना में घटकर 2.35 अरब डॉलर रह गया। अंतरराष्ट्रीय यात्रा और विदेश में शिक्षा पर खर्च कम होने से कुल धनप्रेषण में कमी आई, हालांकि विदेश में निवेश बढ़ने से गिरावट कुछ हद तक थमी है। एलआरएस के तहत कुल धनप्रेषण में अंतरराष्ट्रीय यात्रा की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत होती है। अक्टूबर 2025 में अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर खर्च सालाना आधार पर 7.02 प्रतिशत घटकर 1.35 अरब डॉलर रह गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 1.45 अरब डॉलर था। इसी तरह, विदेश में शिक्षा पर खर्च में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। यह खर्च 26.19 प्रतिशत घटकर 16.33 करोड़ डॉलर रह गया, जो एक साल पहले 22.118 करोड़ डॉलर था। जहां उपभोग से जुड़े खर्च घटे, वहीं विदेश में निवेश के मोर्चे पर मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली। इक्विटी और डेट में निवेश सालाना आधार पर 83 प्रतिशत बढ़कर 27.309 करोड़ डॉलर हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 14.934 करोड़ डॉलर था। इसके अलावा विदेश में अचल संपत्ति की खरीद से जुड़ा धनप्रेषण 78.8 प्रतिशत बढ़कर 4.464 करोड़ डॉलर पहुंच गया। जमा (डिपॉजिट) के लिए भेजे गए धन में भी 20.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। गौरतलब है कि वर्ष 2004 में शुरू की गई एलआरएस योजना के तहत कोई भी भारतीय, अवयस्क सहित, एक वित्त वर्ष में 2.50 लाख डॉलर तक विदेश भेज सकता है। शुरुआत में इसकी सीमा 25,000 डॉलर थी, जिसे समय-समय पर आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बढ़ाया गया।

मीशो के शेयर में चार फीसदी की गिरावट

- कंपनी का मार्केट कैप घटकर लगभग 86,652 करोड़ रह गया

नई दिल्ली । ई-कॉमर्स कंपनी मीशो के शेयर में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में बीएसई पर करीब 4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। 22 दिसंबर को यह शेयर 202.05 रुपये पर लोअर सर्किट में बंद हुआ था। यह लगातार तीसरा कारोबारी दिन है जब शेयर गिरावट में रहा। इस गिरावट के बाद कंपनी का मार्केट कैप घटकर लगभग 86,652 करोड़ रुपये रह गया।

12 से 18 दिसंबर के बीच मीशो के शेयर में जबरदस्त तेजी देखी गई थी और शेयर लगभग 42.5 फीसदी बढ़ा था। शेयर ने बीएसई पर 254.65 रुपये का हाई लेवल भी छू लिया था। मौजूदा गिरावट को लिस्टिंग के बाद हुई तेजी के बाद निवेशकों की प्रॉफिट बुकिंग से जोड़ा जा रहा है। मीशो के शेयर 10 दिसंबर 2025 को लिस्ट हुए थे। आईपीओ प्राइस 111 रुपये था, और अब शेयर लगभग 82 फीसदी ऊपर है। कंपनी के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 81.76 गुना हुआ था। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी वर्तमान में 16.76 फीसदी है।

दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री हुई 18 लाख यूनिट, जीएसटी कटौती का असर

नई दिल्ली ।

नवंबर महीने में दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री सालाना आधार पर करीब 18 लाख यूनिट तक पहुंच गई। बिक्री के आंकडे में आए इस उछाल को जीएसटी कटौती के सकारात्मक असर के रुप में देखा जा रहा है। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है।

जानकारी के मुताबिक, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती और कंपनियों द्वारा डीलरों को दिए गए आकर्षक ऑफर्स के चलते त्योहारी सीजन के बाद भी शोरूम में ग्राहकों की आवाजाही बनी रही, जिससे डीलरों ने इन्वेंट्री दोबारा भरने पर जोर दिया। आईसीआरए का मानना है कि इन सकारात्मक कारकों का असर आगे भी देखने को मिल सकता है। रेटिंग एजेंसी ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2026 में दोपहिया वाहनों की वॉल्यूम ग्रोथ 6 से 9 प्रतिशत के बीच रह सकती है।

इसमें जीएसटी कटौती, शहरी क्षेत्रों में खपत बढ़ने और सामान्य मानसून के चलते ग्रामीण मांग में सुधार से मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, थोक बिक्री के उलट नवंबर में दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। सालाना आधार पर रिटेल बिक्री 9.1 प्रतिशत घटी है। इसकी मुख्य वजह यह बताई गई है कि अक्टूबर में दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जिससे नवंबर में स्वाभाविक गिरावट देखने को मिली।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शादी के मौजूदा सीजन और जीएसटी कटौती के सकारात्मक असर से डीलरों को ग्राहकों से लगातार अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री में नवंबर में सालाना आधार पर 1.4 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई और इनकी बिक्री 1,17,335 यूनिट रही। वित्त वर्ष 2026 के पहले आठ महीनों में कुल दोपहिया बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 6-7 प्रतिशत पर स्थिर बनी हुई है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीए) के आंकड़ों के अनुसार, खुदरा बिक्री में सुधार के चलते इन्वेंट्री का स्तर भी बेहतर हुआ है। सितंबर के अंत में जहां इन्वेंट्री करीब 60 दिनों की थी, वहीं नवंबर 2025 तक यह घटकर 44-46 दिनों पर आ गई।

भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में संस्थागत निवेश 10 अरब डॉलर से अधिक होगा

मुंबई।

भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में संस्थागत निवेश 2025 में 10 अरब डॉलर से अधिक होगा है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में रियल एस्टेट में कुल 77 लेनदेन देखने को मिले हैं और इस दौरान कुल 10.4 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। यह लगातार दूसरा साल है, जब रियल एस्टेट में रिकॉर्ड निवेश हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया हैं कि यह आंकड़ा बीते साल के मुकाबले 17 प्रतिशत अधिक है और 2024 में सेक्टर में कुल संस्थागत निवेश 8.9 अरब डॉलर रहा था।

2025 में निवेश के अलावा कुल 11.43 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता देखने को मिली है और यह निवेश अगले 3-7 वर्षों के दौरान देश के रियल एस्टेट सेक्टर में आएगा। रियल एस्टेट सेक्टर की जानकार ने कहा, ÷2014 के बाद पहली बार, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 52 प्रतिशत की मजबूत बाजार हिस्सेदारी हासिल की है। साथ ही, 2025 में मुख्य परिसंपत्ति अधिग्रहण में दोगुनी वृद्धि यह दिखाती है कि निवेशक न केवल भारत की ग्रोथ स्टोरी पर दांव लगा रहे हैं, बल्कि हमारी स्थिर, आय-सृजन करने वाली संपत्तियों के माध्यम से सक्रिय रूप से दीर्घकालिक संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं। भारतीय आरईआईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविस्ट्स) इस परिवर्तन के प्रमुख घटक के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने 2.5 बिलियन डॉलर का निवेश किया है जो कि मुख्य परिसंपत्ति अधिग्रहण का 56 प्रतिशत है। भारतीय निजी इक्विटी कंपनियों ने भी इसमें अतिरिक्त योगदान दिया है, जो कुल घरेलू पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत है। हालांकि, कुल गतिविधि के प्रतिशत के रूप में विदेशी संस्थागत निवेश में गिरावट आई है, लेकिन कुल विदेशी पूंजी निवेश में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो भारतीय रियल एस्टेट के बुनियादी सिद्धांतों में निरंतर विश्वास को दर्शाता है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

आज से विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते नजर आयेंगे रोहित, विराट और ऋषभ सहित कई सितारे

बेंगलुरु (एजेंसी)। रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत सहित कई स्टार क्रिकेटर बुधवार से यहां शुरु होने वाले घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते दिखेंगे। ये टूर्नामेंट एकदिवसीय प्रारुप में खेला जएगा। ऐसे में इन सभी क्रिकेटरों का इससे अभ्यास का अच्छा अवसर मिलेगा। आजकल एकदिवसीय अंतराष्ट्रीय मैच कम होते हैं , ऐसे में इससे रोहित और विराट को विशेष लाभ होगा कयोंकि इन दोनो ने ही अन्य प्रारुपों से संन्यास ले लिया है। इस टूर्नामेंट से इन दोनो को ही अपनी लय बनाये रखने का अवसर मिलेगा। दोनो का ही लक्ष्य इसमें बेहतर प्रदर्शन कर न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले साल की शुरुआत के लिए होने वाली एकदिवसीय सीरीज के लिए अपनी दावेदारी बरकारार रखना रहेगा।

विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित, विराट और ऋषभ के अलावा शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा भी खेलेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीसी) ने हाल में सभी खिलाड़ियों को फिट होने पर घरेलू क्रिकेट खेलने को कहा था। इसी कारण अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी इसमें खेलते दिख रहे हैं।

रोहित इसमें एक दशक जबकि विराट 15 साल बाद खेलते दिखेंगे। ये दोनो इसलिए भी इसमें खेल रहे हैं ताकि 2027 एकदिवसीय विश्वकप की दौड़ में बने रहें। इन दोनो को पता है कि स्टार खिलाड़ी होने के बाद भी टीम में कई नई प्रतिभाएं हैं, ऐसे में इनपर अपने को बेहतर साबित करने का दबाव रहेगा।

रोहित ने कहा है कि वह मुंबई की तरफ से सिक्किम और उत्तराखंड के खिलाफ जयपुर में 24 और 26 दिसंबर को होने वाले पहले दो मैच खेलेंगे। वहीं कोहली ने अभ्यास किया और कहा कि वह दिल्ली की ओर से दो से तीन मैच खेलेंगे।

दिल्ली एलीट ग्रुप डी में अपना पहला मैच बेंगलुरु में आंध्र के खिलाफ खेलेगा। यह मैच या तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में या बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा। इसके बाद दिल्ली का सामना गुजरात से होगा। कोहली के मंगलवार रात बेंगलुरु पहुंचने के बाद से ही यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह स्टार बल्लेबाज इन दोनों मैच में खेलेगा।

विजय हजारे ट्रॉफी में प्रदर्शन का अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ एकदिवीसीय मैचों के लिए उनके चयन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा पर कोहली और रोहित जानते हैं कि युवा खिलाड़ी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बेहतर प्रदर्शन करना होगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद ईशान किशन की टीम में वापसी से साफ है कि बीसीसीआई घरेलू क्रिकेट के प्रदर्शन पर ध्यान दे रहा है। ऐसे में खराब प्रदर्शन नुकसान देह होगा।

रोहित और कोहली के अलावा कई अन्य स्टा खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे। इसमें दिल्ली के कप्तान ऋषभ और शुभमन जैसे खिलाड़ी हैं। ऋषभ पिछले कुछ समय से सीमित ओवरों के प्रारुप में सफल नहीं रहे हैं। ऐसे में वह इस टूर्नामेंट में अधिक से अधिक रन बनाना चाहेंगे। यही हाल शुभमन का भी है। वह भी टेस्ट क्रिकेट की टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं पर सीमित ओवरों की रन नहीं बना पा रहे हैं। इसी कारण ऋषभ की तरह व भी टी20 विश्वकप से वह बाहर है। अब ये दोनो ही बेहतर प्रदर्शन कर चयनकर्तओं के सामने आने को साबित करना चाहेंगे। करके राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। इस ऋषभ ने अगस्त 2024 के बाद से एकदिवसीय या टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में नहीं खेला है।

वहीं शुभमन को भी उपकप्तान होने के बाद भी टी20 टीम से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में उनका लक्ष्य भी अधिक से अधिक रन बनाना रहेगा। वह पंजाब की ओर से खेलते हुए हुए बेहतर प्रदर्षन करना चाहेंगे। करेगा। गिल के लिए यह अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज से पहले एक अच्छा अभ्यास होगा, जिसमें वह भारत की कप्तानी करेंगे। इस टूर्नामेंट में चयनकर्ताओं की निगाह तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन पर भी टिकी रहेगी।

वहीं भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद के अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और आकाश दीप के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी रही है। ऐसे में ये भी बेहतर प्रदर्शन कर भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करने की दावेदारी पेश करेंगे।

पीएम मोदी से मिले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा... पत्नी भी रही मौजूद

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास (7) से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां उन्होंने भारतीय स्टार भाला फेंक खिलाड़ी और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर की मेजबानी की। तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ी के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत करते दिख रहे है।

बात दें कि नीरज भारत के सबसे प्रतिष्ठित एथलीटों में से एक हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा के लिहाज से 2025 का साल उनके लिए मिला-जुला रहा। उनके सीज़न की एक बड़ी उपलब्धि दोहा डायमंड लीग में दिखाई दी। जहां उन्होंने 90 मीटर का बहुप्रतीक्षित आंकड़ा छू लिया। 90.23 मीटर का उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो एक व्यक्तिगत उपलब्धि थी, हालांकि यह स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर के बेहतर थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जिससे नीरज को दूसरे स्थान पर रहना पड़ा है।

हार के बावजूद, नीरज ने अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पेरिस डायमंड लीग और ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक दोनों में जीत हासिल की। डायमंड लीग सीजन के दौरान, वे दौड़ रैंकिंग में कुल मिलाकर दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि, विश्व चैंपियनशिप 27 वर्षीय नीरज चोपड़ा के लिए एक चुनौतीपूर्ण दौर साबित हुई।

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से दूर, नीरज को 2025 में भी जश्न मनाने के कारण मिले। उन्होंने बेंगलुरु में पहले नीरज चोपड़ा क्लासिक की मेजबानी की, जिसमें दुनिया भर के एथलीटों ने भाग लिया। घरेलू मैदान पर प्रतिस्पर्धा करते हुए, उन्होंने 86.18 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ टूर्नामेंट जीता, जबकि जूलियस येगो और रमेश पथिरागे क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

नोवाक जोकोविच ने चुना अनोखा ट्रेनिंग पार्टनर, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की तैयारी तेज

माल्टा (एजेंसी)। एटीपी टूर के दिग्गज नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की तैयारी के लिए अपने ऑफ-सीजन में एक नए और अप्रत्याशित ट्रेनिंग पार्टनर के साथ अभ्यास शुरू किया है। 36 वर्षीय सर्बियाई स्टार अपने करियर के अंतिम पड़ाव में होने के बावजूद लगातार शीर्ष पर बने रहने की कोशिश में हैं।

जोकोविच ने चुना युवा फ्रेंच खिलाड़ी

जोकोविच ने 23 वर्षीय फ्रेंच खिलाड़ी आर्थर काजॉक्स के साथ ट्रेनिंग शुरू की है। काजॉक्स ने इंस्टाग्राम पर लिखा, %तीन शानदार दिन, ट्रेनिंग, सीखने और ञ्चस्त्रद्बश्वद्गह्लठ्ठश्वद्द के साथ अनुभव साझा करने का अवसर मिला। बहुत आभारी हूं।% यह साझेदारी इस लिहाज से भी हैरान करने वाली है कि काजॉक्स अभी टूर पर अपेक्षाकृत नया खिलाड़ी हैं।

आर्थर काजॉक्स का 2025 में प्रदर्शन

काजॉक्स ने 2025 में अपनी करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 58 हासिल की। उन्होंने किट्ज़बुहेल ञ्जक्कफाइनल में खेलते हुए उल्लेखनीय खिलाड़ियों को हराया और ग्रैंड स्लैम स्तर पर ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन में दो जीत दर्ज की। इस प्रदर्शन ने उन्हें जोकोविच के लिए एक आकर्षक ट्रेनिंग पार्टनर बना दिया।

ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का कमाल, टी20आई गेंदबाजों की रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थान

दुबई (एजेंसी)। भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने घरेलू मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने करियर में पहली बार टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। वहीं दूसरी ओर, आईसीसी की वेबसाइट के अनुसार, आयरलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की वनडे सीरीज के समापन के बाद, दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वाड ने वनडे बल्लेबाज के रूप में नंबर 1 स्थान पुनः प्राप्त कर लिया है, जो हाल ही में स्मृति मंधाना ने उनसे छीना था।

ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड अगस्त से टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज थीं, लेकिन विशाखापत्तनम में श्रीलंका के खिलाफ दीप्ति के चार ओवरों में 1/20 के हालिया स्पेल ने भारतीय स्टार को शीर्ष पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीप्ति ने भारत की आठ विकेट की जीत से पांच रेटिंग अंक अर्जित किए और 28 वर्षीय खिलाड़ी अब टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर अपनी ऑस्ट्रेलियाई प्रतिद्वंद्वी से एक अंक की मामूली बढ़त बनाए हुए हैं।

वनडे बल्लेबाजों की नवीनतम रैंकिंग में मंधाना दूसरे स्थान पर खिसक गई हैं, वहीं वोल्वाड्ट ने आयरलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर खेली गई दक्षिण अफ्रीका की तीन मैचों की वनडे श्रृंखला के अंतिम मैच में शानदार शतक लगाकर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। वोल्वार्ड्ट ने आयरलैंड के खिलाफ खेले गए अंतिम दो मैचों में शतक बनाए और प्रोटियाज ने श्रृंखला 3-0 से जीत ली। दक्षिण अफ्रीका की बेहद सुसंगत कप्तान ने अपने करियर की नई उच्चतम रेटिंग हासिल की और एक स्थान ऊपर चढ़कर मंधाना को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान पर पहुंच गईं।

उनकी साथी खिलाड़ी अरुंधति रेड्डी (पांच स्थान ऊपर चढ़कर 36वें स्थान पर) ने भी श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच के बाद टी20द्ब गेंदबाजों की रैंकिंग में बढ़त हासिल की है, वहीं उनकी हमवतन जेमिमा रोड्रिग्स टी20आई बल्लेबाजों की नवीनतम सूची में सबसे आगे हैं, जो पांच स्थान ऊपर चढ़कर नौवें स्थान पर पहुंच गई हैं। रोड्रिग्स ने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद अर्धशतक लगाकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता और वह टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों की शीर्ष 10 सूची में शामिल हो गईं, जहां वह साथी भारतीय खिलाड़ी मंधाना (तीसरे स्थान पर) और शेफाली वर्मा (10वें स्थान पर) के साथ शामिल हो गईं।

बीसीसीआई ने अंडर-19 एशियाकप में खराब प्रदर्शन पर कोच और कप्तान से जवाब मांगा

मुम्बई ।भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने एशिया कप अंडर-19 के फाइनल में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन पर टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे और टीम के मुख्य कोच ऋषिकेश कानिटकर से जवाब मांगा है।भारतीय टीम को फाइनल में करारी हार का सामना करना पड़ा था जिससे प्रशंसकों में निराशा का भाव है।इसके बाद से ही बीसीसीसी के सभी सदस्यों ने टीम के कमजोर प्रदर्शन की समीक्षा की मांग की थी।जिसे बीसीसीसी ने मान लिया है। फाइनल में भारतीय टीम को 191 रनों से हार मिली थी।उसके बल्लेबाज और गेंदबाज दोनो ही विफल रहे थे। वहीं इससे पहले के सभी मैच भारतीय टीम जीती थी।ग्रुप स्तर पर हावी रही भारतीय टीम ने तब पाक को भी हराया था पर फाइनल में वह नाकाम रही।ये समीक्षा इसलिए भी की गयी ताकि अगले साल 2026 में होने वाले अंडर-19 विश्व कप से पहले टीम को हो रही परेशानी को हल किया जाये। पाकिस्तान की टीम ने फाइनल में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनो में ही प्रभाव जमाया और भारतीय टीम को कोई अवसर नहीं दिया।भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने पाक ने 347 रन बनाये और इसके बाद भारतीय टीम को 26 ओवरों में ही समेट दिया।

सुनील गावस्कर को मिली पर्सनैलिटी राइट्स की कानूनी सुरक्षा, बने पहले स्पोर्ट्सपर्सन

नई दिल्ली।भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने इतिहास रचते हुए पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की न्यायिक सुरक्षा पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है।दिल्ली हाई कोर्ट के इस अहम फैसले ने न केवल खेल जगत बल्कि डिजिटल कानून और सेलिब्रिटी अधिकारों के क्षेत्र में भी एक नई मिसाल कायम की है।यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मशहूर हस्तियों की पहचान का दुरुपयोग तेजी से बढ़ रहा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनील गावस्कर के नाम, तस्वीर और पहचान के कथित गलत इस्तेमाल को लेकर सख्त रुख अपनाया।कोर्ट ने आदेश दिया कि सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी उल्लंघनकारी पोस्ट, वीडियो और संबंधित कंटेंट को 72 घंटे के भीतर हटाया जाए।साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि संबंधित अकाउंट या यूजर ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी होगी कि वे स्वयं ऐसे कंटेंट को हटाएं।

नये साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड से एकदिवसीय और टी20 सीरीज खेलेगी भारतीय टीम

मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम अब नये साल में ही मैदान में उतरेगी। भारतीय टीम को नये साल की शुरुआत में अपनी ही धरती पर न्यूजीलैंड से तीन एकदिवसीय और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। इस सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से होगी। इस दौरान भारतीय टीम को आठ अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने हैं। टीम का पहला एकदिवसीय मैच 11 जनवरी को वडोदरा में जबकि दूसरा 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा वहीं तीसरा और अंतिम एकदिवसीय मैच 18 दिसंबर को इंदौर में खेला जाएंगा। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1़30 बजे से खेले जाएंगे।

एकदिवसीय सीरीज के बाद टी20 मैचों की सीरीज होगी। इससे भारतीय टीम को फरवरी में अपनी ही धरती पर खेले जाने वाले टी20 विश्वकप के लिए अभ्यास का अवसर मिलेगा। विश्वकप से पहले इस सीरीज से भारतीय टीम को अभ्यास का अंतिम अवसर मिलेगा। सीरीज का पहला टी20 मैच 21 जनवरी को नागपुर में खेला जाएगा जबकि दूसरा मैच 23 जनवरी को रायपुर में होगा ! तीसरा टी20 भारत 25 जनवरी को गुवाहाटी में खेलेगा वहीं चौथा मैच 28 को विशाखापत्तनम में जबकि सीरीज का पांचवां और आखिरी टी20 मैच 31 जनवरी 2026 को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। ये सभी मैच शाम 7़00 बजे से खेले जाएंगे। इसके बाद भारतीय टीम विश्व कप में खिताब बरकरार रखने उतरेगी।

आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभी तक 120 एकदिवसीय मैच खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम ने 62 जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैच जीते हैं। वहीं सात मैचों का परिणाम नहीं निकला है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 25 टी20 अंतराष्ट्रीय मैच खेले गये हैं। इसमें 14 में भारतीय टीम। वहीं 10 में न्यूजीलैंड जीती है जबकि एक मैच टाई रहा है।टी20 विश्वकप ओर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम उतरेगी।

किरण अंकुश जाधव ने राष्ट्रीय शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल का जीता स्वर्ण

भोपाल ।नेवी के किरण अंकुश जाधव ने मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं के तहत 10 मीटर एयर राइफल पुरुष फाइनल में संयमित और निरंतर प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया।जाधव ने 252.1 अंकों के साथ प्रतियोगिता समाप्त की और ओलंपियन अर्जुन बाबूता को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 251.4 अंकों के साथ रजत पदक जीता।मौजूदा 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन्स राष्ट्रीय चैंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 229.8 अंकों के साथ कांस्य पदक हासिल किया।रेलवे के शहू तुषार माने 209.3 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे।उनके बाद हिमांशु ने 181.1, रमायणा तोमर ने 166.7, ओंकार विकास वाघमारे ने 145.4 और प्रदीप सिंह ने 123.3 अंकों के साथ फाइनल लाइन-अप पूरा किया।10 मीटर एयर राइफल पुरुष जूनियर फाइनल में गुजरात के मोहम्मद मुरतजा वानिया ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए 254.3 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता।पश्चिम बंगाल के अभिनव शॉ ने 251.6 अंकों के साथ रजत पदक हासिल किया, जबकि कर्नाटक के ओंकार विकास वाघमारे ने 230.1 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता।कर्नाटक के नारायण प्रणव 209 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे, जिन्हें ओंकार के साथ शूट-ऑफ का सामना करना पड़ा।दिव्यांशु शैलेंद्र देवांगन 187.5 अंकों के साथ पांचवें और पार्थ माने 166.9 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहे, जहां पार्थ भी शूट-ऑफ के बाद बाहर हुए।उमा महेश मद्दिनेनी ने 145.3 और हिमांशु ने 123 अंकों के साथ फाइनलिस्ट सूची पूरी की। 10 मीटर एयर राइफल पुरुष यूथ फाइनल में ओंकार विकास वाघमारे ने अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए 250 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता।उन्होंने अंतिम शॉट्स में निर्णायक बढ़त बनाते हुए अपने ही राज्य के नारायण प्रणव को 0.3 अंकों से पीछे छोड़ा, जिन्हें रजत पदक मिला। तमिलनाडु के शक्तिवेल सेंथिवेल ने 229.5 अंकों के साथ कांस्य पदक हासिल किया। पार्थ माने 208.2 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे, जबकि अभिनव शॉ ने 187.3 और प्रीतम केंद्रे ने 166.4 अंकों के साथ क्रमश- पांचवां और छठा स्थान हासिल किया। अबिषेक सेखर ने 145.2 और रितेश रविंद्र घुले ने 123.1 अंकों के साथ अन्य फाइनलिस्ट के रूप में प्रतियोगिता समाप्त की।पदक वितरण समारोह का आयोजन विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर एनआरएआई के महासचिव पवनकुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

भारत एफआईएच विश्व रैंकिंग में आठवें स्थान पर फिसला, महिला टीम 10वें स्थान पर

लुसाने (स्विट्जरलैंड) (एजेंसी)। भारत 2025 की शुरुआत पांचवें स्थान पर करने के बाद साल के अंत तक जाते-जाते FIH विश्व रैंकिंग में आठवें स्थान पर फिसल गया है जबकि महिला टीम 10वें स्थान पर है। 2025 में इंटरनेशनल हॉकी ने टॉप लेवल के एक्शन का एक लगातार कैलेंडर पेश किया - FIH हॉकी प्रो लीग की लड़ाइयों से लेकर नेशंस कप और नेशंस कप 2 के रोमांच के साथ-साथ सभी महाद्वीपों में कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप तक - जिससे एफआईएच वर्ल्ड रैंकिंग में बड़े बदलाव हुए।

पुरुषों और महिलाओं दोनों के खेल में, जानी-मानी टीमों ने अपनी स्थिति मजबूत की, जबकि उभरती हुई टीमों ने महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। महिलाओं की रैंकिंग में, नीदरलैंड्स (3809) जिसने साल की शुरुआत टॉप स्थान पर की थी, उसने पूरे साल अपनी पकड़ बनाए रखी, एक और शानदार सीजन के साथ जिसमें उन्होंने प्रो लीग और यूरोहॉकी चैंपियनशिप में चैंपियनशिप जीतकर अपनी कैबिनेट में और ट्रॉफियां जोड़ीं, जबकि अर्जेंटीना (3326), बेल्जियम (3109) और चीन (2977) ने शानदार कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और प्रो लीग अभियानों के साथ क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर बने रहे, जहां से उन्होंने साल की शुरुआत की थी।

स्पेन (2777) टॉप-10 रैंकिंग में साल के सबसे बड़े फायदे में रहने वालों में से है, क्योंकि वे पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि साल की शुरुआत आठवें स्थान पर की थी ! स्पेन की यह बढ़त ऑस्ट्रेलिया (2758), जर्मनी (2734) और इंग्लैंड (2510) की कीमत पर हुई है, जो सभी एक-एक स्थान नीचे गिर गए हैं, और साल का अंत छठे, सातवें और आठवें स्थान पर किया है। न्यूजीलैंड (2319) जिसने 2025 में महिलाओं का एफआईएच हॉकी नेशंस कप और ओसनिया कप जीता था, वह भारत (2315) से ऊपर नौवें स्थान पर पहुंच गया है, जिसे 2025 में प्रो लीग से बाहर होना पड़ा था।

जापान (2186) और संयुक्त राज्य अमेरिका (2172) दो स्थान ऊपर चढ़कर ग्यारहवें और बारहवें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि आयरलैंड (2030) और चिली (1999) तेरहवें और पंद्रहवें स्थान पर आ गए हैं, स्कॉटलैंड (2015) चौदहवें स्थान पर है। कोरिया (1864) सोलहवें स्थान पर बना हुआ है, उसके बाद फ्रांस (1742) है जिसकी एफआईएच हॉकी नेशंस कप 2 में जीत ने उसे तीन स्थान ऊपर चढ़ने में मदद की। इटली (1737), उरुग्वे (1736) और दक्षिण अफ्रीका (1670) टॉप-20 में शामिल हैं, जबकि कनाडा (1668) और मलेशिया (1667) बस थोड़ा ही पीछे हैं !

पुरुषों की रैंकिंग में नीदरलैंड (3376) और बेल्जियम (3225) टॉप दो स्थानों पर बने हुए हैं, लेकिन साल की शुरुआत की तुलना में नीचे काफी बदलाव हुए हैं ! जर्मनी (3116) एक सफल यूरोहॉकी अभियान के बाद एक स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे स्थान पर आ गया है, उसके बाद अर्जेंटीना (3022) है जो साल की शुरुआत में आठवें स्थान पर रहने के बाद चौथे स्थान पर आ गया है ! ऑस्ट्रेलिया (3007) और स्पेन (2995) पांचवें और छठे स्थान पर एक-एक स्थान ऊपर चढ़े हैं, उसके बाद इंग्लैंड (2864) और भारत (2845) हैं जिन्हें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जो साल की शुरुआत में क्रमशः तीसरे और पांचवें स्थान पर थे।

फ्रांस (2371) नौवें स्थान पर बना हुआ है, जबकि न्यूजीलैंड (2254) और आयरलैंड (2246) ने साल की शुरुआत से एक-दूसरे के साथ जगह बदली है। दक्षिण अफ्रीका (2127) और मलेशिया (2097) बारहवें और तेरहवें स्थान पर स्थिर हैं। एफआईएच हॉकी प्रो लीग में प्रमोशन के बाद, पाकिस्तान (2034) चौदहवें स्थान पर एक स्थान ऊपर चढ़ गया है, उसके बाद वेल्स (1989) और कोरिया (1981) हैं। मिस्र (1956) जिसने एफआईएच हॉकी नेशंस कप 2 में शानदार डेब्यू किया था, इस साल सबसे ज्यादा ऊपर चढ़ने वाली टीमों में से एक है, जो सत्रहवें स्थान पर है।

जापान (1982), कनाडा (1863) और स्कॉटलैंड (1843) टॉप-20 में शामिल हैं, जबकि ऑस्ट्रिया (1805), चिली (1727), चीन (1723), पोलैंड (1694) और संयुक्त राज्य अमेरिका (1690) अगले पांच स्थानों पर हैं। एफआईएच ने 1 जनवरी 2020 को जो रैंकिंग कैलकुलेशन मॉडल पेश किया, वह पिछले टूर्नामेंट-आधारित रैंकिंग सिस्टम से हटकर एक डायनामिक, मैच-आधारित तरीके पर आ गया है, जहाँ विरोधी टीमें ऑफिशियल,एफआईएच द्वारा मंजूर किए गए गेम्स में पॉइंट्स का आदान-प्रदान करती हैं। एक्सचेंज किए जाने वाले पॉइंट्स की संख्या मैच के नतीजे, टीमों की रिलेटिव रैंकिंग और मैच के महत्व पर निर्भर करती है।

चिन्नास्वामी स्टेडियम को विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय मैच के आयोजन की अनुमति नहीं मिली

बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 24 दिसंबर को दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय मैच के आयोजन की अनुमति नहीं मिली है।पुलिस आयुक्त सीमंत कुमार सिंह ने कह है कि आयोजकों ने मैच आयोजित करने की अनुमति मांगी थी पर उसे स्वीकार नहीं किया गया है।वहीं इससे पहले राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने स्टेडियम में क्रिकेट मैचों के आयोजन की अनुमति देने पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था।समिति ने सोमवार को स्टेडियम का दौरा किया था और इसके बाद मैच की अनुमति नहीं दिये जाने की सलाह दी । पुलिस आयुक्त ने कहा, 'समिति ने कल स्टेडियम का दौरा किया था और उसकी सिफारिश पर मैच खेलने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया।इसलिए वहां कोई मैच नहीं होगा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

बिनाका गीतमाला का केंद्र रही श्रीलंका रेडियो सेवा के 100 वर्ष पूरे

कोलंबो, एजेंसी। हिंदी फिल्म संगीत को बिनाका गीतमाला जैसे अनूठे साप्ताहिक कार्यक्रम के जरिये लोकप्रिय बनाने वाली श्रीलंका की रेडियो सेवा ने इस हफ्ते अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए। श्रीलंका की यह रेडियो सेवा पूरे भारत में कभी रेडियो सीलोन के नाम से लोकप्रिय थी। श्रीलंका की रेडियो सेवा आधिकारिक तौर पर 16 दिसंबर, 1925 को शुरू की गई थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, यह एशिया का पहला व्यावसायिक शॉर्ट-वेव स्टेशन था। हांगकांग में बदमाशों ने चाकू की नोक पर 6.4 अरब डॉलर लूटे हांगकांग , एजेंसी। हांगकांग में चाकू की नोक पर 6.4 अरब डॉलर की लूट मामले में चीन के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, घटना शुंग वान क्षेत्र में मनी एक्सचेंज शॉप में हुई। उस समय दो कर्मचारियों से तीन बदमाशों ने चाकू की नोक पर रुपयों से भरे चार सूटकेस लूट लिए। कर्मचारी यह राशि बैंक में जमा कराने जा रहे थे। पुलिस को संदिग्धों का फरार वाहन मिल गया है। लूट में कुल चार लोग शामिल थे। हालांकि, केवल 43 वर्षीय एक शख्स ही पकड़ा गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

नेपाल में विश्व ध्यान दिवस पर विशेष कक्षाएं, 50 हजार लोगों ने किया ध्यान

काठमांडो, एजेंसी। विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर रविवार को नेपाल में विशेष कक्षाएं आयोजित की गईं। आर्ट ऑफ लिविंग की नेपाल इकाई की तरफ से देशभर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में एक सप्ताह तक चले कार्यक्रम में 50 हजार से अधिक लोगों ने ध्यान अभ्यास किया। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से घोषित विश्व ध्यान दिवस हर वर्ष 21 दिसंबर को विश्वभर में मनाया जाता है। इस बार दूसरा विश्व ध्यान दिवस था। आर्ट ऑफ लिविंग नेपाल के अनुसार, देश के विभिन्न विद्यालयों, कॉलेजों, शैक्षिक संस्थानों, सरकारी व निजी कार्यालयों, पुलिस, नेपाली सेना की इकाइयों तथा सामुदायिक केंद्रों में ध्यान सत्र आयोजित किए गए। इसके अलावा, एक हजार से अधिक प्रतिभागियों ने सात दिवसीय विशेष ध्यान अभ्यास पूरा किया। आयोजकों के अनुसार, सभी सत्र प्रशिक्षित शिक्षकों व स्वयंसेवकों के सहयोग से संचालित किए गए। मुख्य कार्यक्रम काठमांडो के शंखमूल स्थित आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सुधा शर्मा ने बदलती जीवनशैली, तनाव, चिंता व अवसाद के कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि होने की बात कही। उन्होंने इन समस्याओं की रोकथाम और प्रबंधन में ध्यान की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

पाकिस्तान को मिला तुर्किये की चापलूसी का इनाम, नौसेना में शामिल हुआ युद्धपोत पीएनएस खैबर

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तानी नौसेना को तुर्किये की चापलूसी का इनाम मिला है। तुर्किये में बनाया गया दूसरा एमआईएलजीईएम श्रेणी का जहाज रविवार को इस्लामाबाद को मिल गया है। यह जहाज दोनों देशों के बीच तकनीक हस्तांतरण समझौते क तहत बनाया गया है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा ने एक बयान में कहा, इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में आयोजित एक समारोह में पीएनएस खैबर को कमीशन किया गया। तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तईब एर्दोआन और पाकिस्तान की नौसेना के प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ इस समारोह में मौजूद थे। बयान में दावा किया गया कि पीएन एमआईएलजीईएम जहाज आधुनिक तकनीक वाले सतह युद्धपोत हैं। ये जहाज नवीनतम कमान एवं नियंत्रण प्रणाली से लैस हैं, जिन्हें आधुनिक हथियारों और सेंसर्स के साथ जोड़ा गया है।

मुनीर बोले- भारत से जंग में अल्लाह की मदद मिली:नहीं तो हालात बिगड़ जाते

मई में भारत ने 11 पाकिस्तानी एयरबेस तबाह किए थे

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत के साथ मई में हुए सैन्य संघर्ष में अल्लाह की मदद मिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हमने इसे महसूस किया?, जिसकी वजह से हालात पूरी तरह बिगड़ने से बच गए। मुनीर ने यह बयान 10 दिसंबर को इस्लामाबाद में हुई नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस में दिया। उनके भाषण के वीडियो क्लिप रविवार को लोकल टीवी चैनलों पर दिखाए गए।

भारत ने 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच चार दिन तक भारी गोलीबारी और सैन्य टकराव हुआ, जो 10 मई को समझौते के बाद रुका। संघर्ष के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए थे।

मुनीर बोले- इस्लामी देशों में पाकिस्तान का खास दर्जा- अपने भाषण में मुनीर ने धार्मिक बातों पर जोर देते हुए पाकिस्तान की तुलना 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद द्वारा स्थापित इस्लामी राज्य से की।

उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ीं और कहा कि इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान को खास दर्जा मिला है। मुनीर ने कहा कि दुनिया में 57 इस्लामी देश हैं, लेकिन अल्लाह ने पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन यानी मक्का और मदीना की हिफाजत का सम्मान दिया है।

कहा- अफगानिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से एक को चुने- मुनीर ने पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा हालात पर भी बात की और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से कहा कि वह पाकिस्तान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) में से किसी एक को चुने। मुनीर का आरोप है कि पाकिस्तान में घुसपैठ करने वाले ञ्ज्ञक्क के आतंकियों में करीब 70% अफगान हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या पाक नागरिकों के खून के लिए अफगानिस्तान जिम्मेदार नहीं है। मुनीर ने यह भी कहा कि किसी इस्लामी देश में जिहाद का ऐलान करने का अधिकार सिर्फ उस देश को होता है। बिना सरकार की इजाजत कोई फतवा जारी नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान की ज्यादातर आंतरिक समस्याओं के लिए अफगानिस्तान से आए हुए लोग जिम्मेदार हैं।

आसिम मुनीर पहले भी कट्टरपंथी बयान दे चुके हैं- आसिम मुनीर पहले भी कई बार कट्टरपंथी बयान दे चुके हैं। उन्होंने इसी साल अप्रैल में कहा था कि पाकिस्तान की नींव कलमे (इस्लाम धर्म का मूल मंत्र) पर रखी गई है। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति-रिवाज अलग हैं। हमारी संस्कृति और सोच अलग है। यही टू-नेशन थ्योरी की नींव थी। हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हम हिंदुओं से अलग हैं। हमारी सोच, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। इसी वजह से हम दो देश हैं, एक देश नहीं हैं।

इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है। जनरल मुनीर ने कहा था- आज तक सिर्फ दो रियासतों की बुनियाद कलमे पर पड़ीं। पहली रियासत-ए-तैयबा, क्योंकि तैयबा को हमारे नबी (मोहम्मद साहब) ने नाम दिया था। आज उसे मदीना कहते हैं। वहीं, दूसरी रियासत 1300 साल बाद अल्लाह ने पाकिस्तान बनाई।

4 दिसंबर को सीडीएफ नियुक्त हुए पाकिस्तान सरकार ने 4 दिसंबर को आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (सीडीएफ) और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (सीओएएस) नियुक्त किया था। दोनों पदों पर उनका कार्यकाल पांच साल का होगा। मुनीर पाकिस्तान के पहले सैन्य अधिकारी हैं जो एकसाथ सीडीएफ और सीओएएस दोनों पद संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नियुक्ति की सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को समरी भेजी थी। मुनीर को इसी साल फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया था।

पाकिस्तानी संसद ने 12 नवंबर को सेना की ताकत बढ़ाने वाला 27वां संवैधानिक संशोधन पास किया था। इसके तहत मुनीर को सीडीएफ बनाया गया। इस पद के मिलते ही उन्हें पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी मिल गई यानी वे देश के सबसे ताकतवर शख्स बन गए हैं। दरअसल 29 नवंबर 2022 को जनरल आसिम मुनीर को सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। उनका मूल कार्यकाल तीन साल का था, यानी 28 नवंबर 2025 को खत्म हो गया।

इंडोनेशिया में बस एक्सीडेंट में 15 लोगों की मौत, 34 लोग सवार थे

जकार्ता, एजेंसी। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर आधी रात के बाद एक पैसेंजर बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बस में कुल 34 लोग सवार थे। ड्राइवर टोल रोड पर बस से कंट्रोल खो बैठा, जिसके बाद बस एक कंक्रीट की दीवार से टकराई, फिर पलटकर सड़क किनारे गिर गई।

रेस्क्यू एजेंसी के प्रमुख बुडियोनों ने बताया कि यह इंटर स्टेट बस राजधानी जकार्ता से देश के ऐतिहासिक शहर योग्या जा रही थी। हादसा होते ही बचाव कार्य शुरू कर दिया गया।

10 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा- पुलिस ने बताया कि हादसे का शिकार हुई बस राजधानी जकार्ता से प्राचीन शाही शहर योग्यकार्ता जा रही थी। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुडियोनो ने कहा, 'तेज टक्कर से कई यात्री बाहर गिर गए और बस की बॉडी में फंस गए।

' पुलिस और बचाव दल दुर्घटना के लगभग 40 मिनट बाद पहुंचे और घटनास्थल पर मारे गए छह यात्रियों के शव बरामद किए। बुडियोनो ने बताया कि अन्य 10 लोगों की अस्पताल ले जाते समय या इलाज के दौरान मौत हो गई।

घायलों में से कई की हालत गंभीर- हादसे में 18 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से पांच की हालत गंभीर है और 13 अन्य लोग भी गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया गया कि पीली बस अपने किनारे पर पलटी हुई थी और नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के कर्मियों, पुलिस और राहगीरों से घिरी हुई थी, जबकि एम्बुलेंस पीड़ितों और मृतकों को ले जा रही थी।

दक्षिण अफ्रीका में शराबखाने के पास मास शूटिंग, 10 की मौत, 10 घायल

जोहान्सबर्ग , एजेंसी। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रविवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, हमले का मकसद फिलहाल स्पष्ट नहीं है। गौतेंग प्रांत की पुलिस प्रवक्ता ब्रिगेडियर ब्रेंडा मुरीडिली ने बताया कि कुछ पीड़ितों को सड़कों पर अचानक गोली मारी गई। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। यह गोलीबारी बेकर्सडाल के एक शराबखाने के पास हुई। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश जारी है।

यह इस महीने दक्षिण अफ्रीका में दूसरी बड़ी गोलीबारी की घटना है। इससे पहले 6 दिसंबर को राजधानी प्रिटोरिया के पास एक हॉस्टल में हुई फायरिंग में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें एक तीन साल का बच्चा भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक, उस हॉस्टल में अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। 6.3 करोड़ की आबादी वाले दक्षिण अफ्रीका में अपराध की दर बेहद अधिक है और यह दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां हत्या की दर सबसे ज्यादा है।

भूकंप से हिला तिब्बत, 3.5 मापी गई तीव्रता

ल्हासा , एजेंसी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार को तिब्बत में 3.5 तीव्रता का भूकंप आया। एनसीएस ने एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी साझा करते हुए बताया कि भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर भारतीय समयानुसार रात 8:29 बजे आया। 'भूकंप की तीव्रताः 3.5, दिनांकः 21/12/2025, भारतीय समयानुसार रात 8:29:27 बजे, अक्षांशः 28.51 उत्तर, देशांतरः 87.57 पूर्व, गहराईः 10 किमी, स्थानः तिब्बत। इससे पहले 5 दिसंबर को तिब्बत में 3.0 तीव्रता का भूकंप आया था। बता दें कि उथले भूकंप आमतौर पर गहरे भूकंपों की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं। इसका कारण यह है कि उथले भूकंपों से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों को सतह तक पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके परिणामस्वरूप जमीन में अधिक कंपन होता है और इमारतों को अधिक नुकसान और अधिक जानमाल का नुकसान होने की संभावना रहती है। तिब्बती पठार विवर्तनिक प्लेटों के टकराव के कारण अपनी भूकंपीय गतिविधि के लिए जाना जाता है।

नाइजीरिया में अगवा किए गए 130 स्कूली बच्चे और स्टाफ सुरक्षित रिहा : अबुजा, एजेंसी। नाइजीरिया में पिछले महीने अगवा किए गए 130 स्कूली बच्चों और स्कूल स्टाफ को सुरक्षित रिहा कर लिया गया है। पुलिस ने रविवार को इसकी पुष्टि की। 21 नवंबर को हथियारबंद लोगों ने नाइजर राज्य के सेंट मैरी कैथोलिक स्कूल पर हमला कर कम से कम 303 बच्चों और 12 शिक्षकों का अपहरण कर लिया था। घटना के कुछ घंटों बाद 50 बच्चे भागने में सफल रहे थे, जबकि इस महीने की शुरुआत में 100 बच्चों को रिहा किया गया था। पुलिस के अनुसार, अब बाकी बचे सभी 130 पीड़ितों को भी छोड़ दिया गया है। इनमें स्कूल का स्टाफ भी शामिल है। राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि बच्चों को सोमवार को राज्य की राजधानी मिना लाया जाएगा, जहां वे क्रिसमस से पहले अपने परिवारों से मिल सकेंगे। सरकार ने कहा कि यह रिहाई सेना और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई के बाद संभव हुई। हालांकि, अब भी कुछ बच्चों और शिक्षकों की स्थिति को लेकर पूरी जानकारी साझा नहीं की गई है।

फिलीपींस ने चीनी आयात पर ब्रेक बढ़ाया, 2026 तक रहेगा प्रतिबंध : मनीला, एजेंसी। फिलीपींस सरकार ने चीनी आयात पर लगे प्रतिबंध को दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। देश के कृषि विभाग ने कहा कि घरेलू चीनी उत्पादन में सुधार और बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आयात पर रोक को और लंबी अवधि के लिए जारी रखना जरूरी है। कृषि मंत्री फ्रांसिस्को तिउ लॉरेल ने कहा,चीनी उत्पादन और मांग के मौजूदा आकलन के आधार पर, पहले सुझाई गई अवधि से ज्यादा लंबे आयात प्रतिबंध की आवश्यकता है।उन्होंने बताया कि देश में कच्ची चीनी का घरेलू उत्पादन मजबूत हुआ है, इसलिए सरकार की प्राथमिकता स्थानीय चीनी को बढ़ावा देना और बाजार को स्थिर बनाए रखना है। बतौर शुगर बोर्ड के अध्यक्ष, तिउ लॉरेल ने कहा कि शुगर रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन अब रिफाइनरियों की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखेगा, ताकि स्टैंडर्ड और प्रीमियम रिफाइंड शुगर के भंडार की सटीक जानकारी बनी रहे। इस बीच, फिलीपींस सांख्यिकी प्राधिकरण ने 9 दिसंबर को जारी आंकड़ों में बताया कि अक्टूबर महीने में देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत हुआ है। उत्पादन मूल्य सूचकांक में सालाना आधार पर 1.7त्न की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं उत्पादन मात्रा सूचकांक भी बढ़कर 1.4 प्रतिशत हो गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों के निर्माण से आया, जिसमें 16.8त्न की तेज वृद्धि दर्ज हुई।

इस्राइली सेना ने गाजा युद्धविराम का उल्लंघन करने वाले आतंकवादियों पर बरसाई गोलियां

गाजा, एजेंसी। इस्त्राइली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने बताया कि रविवार सुबह उत्तरी गाजा पट्टी में तैनात यरुशलम ब्रिगेड की लड़ाकू टीम के जवानों ने येलो लाइन के पास जमा हुए कुछ संदिग्धों की पहचान की और उन्हें तितर-बितर करने के लिए गोलियां चलाईं। गोलियां चलाने के बाद, तीन आतंकवादी येलो लाइन पार कर गए और बलों की ओर इस तरह बढ़े, जिससे उन्हें तत्काल खतरा पैदा हो गया। इसके अलावा उत्तरी गाजा पट्टी में दो अन्य घटनाओं में, इस्त्राइली बलों ने येलो लाइन पार करने वाले दो आतंकवादियों की पहचान की और इस तरह बढ़े जिससे उन्हें खतरा पैदा हो गया। तीनों घटनाओं में बलों के निर्देश पर इस्त्राइली वायु सेना ने खतरे को खत्म करने के लिए आतंकवादियों पर हमला किया। आईडीएफ ने यह नहीं बताया कि आतंकवादी मारे गए या घायल हुए। येलो लाइन उन क्षेत्रों को चिह्नित करती है जहांइस्त्राइली बल गाजा युद्धविराम समझौते के तहत कार्रवाई जारी रखे हुए हैं: इज़राइल इस रेखा के पूर्व, उत्तर और दक्षिण में सभी क्षेत्रों को नियंत्रित करता है और हमास और अन्य आतंकवादियों को इसे पार करने की मनाही है। नेपाल हवाई अड्डे पर दो भारतीयों को नशीले पदार्थों के साथ पकड़ा नेपाल के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मादक पदार्थों की तस्करी के सिलसिले में दो भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। रविवार को एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय नागरिक रणजीत सिंह (33) को हवाई अड्डे के आगमन क्षेत्र में 4.284 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि सिंह बैंकॉक से थाई एयरवेज की फ्लाइट से नशीले पदार्थ लेकर आया था, तभी हवाई अड्डे की सुरक्षा और सीमा शुल्क कार्यालयों के पुलिस के एक संयुक्त दल ने सुरक्षा जांच के दौरान उसे रोककर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि एक अन्य भारतीय नागरिक पुनीत शर्मा (33) को भी हवाई अड्डे के पार्किंग क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जब वह प्रतिबंधित सामान लेने के लिए वहां पहुंचा था। दोनों आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए नेपाल पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

ऑस्ट्रेलिया के बीच पर हमला करने वाले बाप-बेटे ने सीक्रेट जगह ट्रेनिंग ली थी

डरबन, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर 14 दिसंबर को हुए आतंकी हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों के मुताबिक, इस हमले के आरोपी बाप-बेटे ने एक गांव के सीक्रेट इलाके में बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ली थी।

दस्तावेज में बताया गया है कि 50 साल के साजिद अकरम और उनके 24 साल के बेटे नवीद अकरम का एक वीडियो मिला है। इस वीडियो में दोनों राइफल और शॉटगन पकड़े हुए नजर आते हैं और ऐसे तरीके से चलते दिखते हैं जैसे किसी खास तरह की ट्रेनिंग ले रहे हों। कोर्ट के मुताबिक, दोनों वीडियो में गोली चलाते और रणनीति के साथ आगे बढ़ते दिखते हैं।

बॉन्डी बीच पर उस समय हमला हुआ था जब वहां यहूदी परिवार हनुक्का का त्योहार मना रहे थे। तभी अचानक गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने मौके पर ही साजिद अकरम को मार गिराया था। उनके बेटे नवीद को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उस पर आतंकवाद का मामला, 15 लोगों की हत्या और 40 लोगों की हत्या की कोशिश के आरोप लगे हैं। कोर्ट के कागजों में यह भी कहा गया है कि गोली चलाने से ठीक पहले पिता और बेटे ने भीड़ की ओर चार देसी बम फेंके थे, लेकिन किस्मत से वे फटे नहीं। इनमें तीन पाइप बम और एक टेनिस बॉल में रखा बम बताया गया है। जांच में सामने आया है कि ये सभी बम फट सकते थे। इसके अलावा, जिस गाड़ी से वे हमले के लिए आए थे उसकी डिक्की में एक और संदिग्ध बम रखा हुआ था। जांच एजेंसियों को कुछ वीडियो भी मिले हैं, जिन्हें दोनों ने खुद रिकॉर्ड किया था। इन वीडियो में वे धार्मिक कट्टर सोच से जुड़ी बातें करते दिखते हैं। एक वीडियो में वे इस्लामिक स्टेट के झंडे की तस्वीर के सामने खड़े होकर बयान देते हैं और अपने हमले को सही ठहराने की कोशिश करते नजर आते हैं। कोर्ट का कहना है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पिता और बेटे ने इस आतंकी हमले की कई महीनों तक बहुत सोच-समझकर योजना बनाई थी। उन्होंने पहले ट्रेनिंग ली, हथियार और बम जुटाए और फिर मौका देखकर इस हमले को अंजाम दिया।

एपस्टीन सेक्स स्कैंडल फाइल्स में ट्रम्प की फोटो फिर अपलोड:इसमें मेलानिया ट्रम्प की भी तस्वीर

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिका की राजनीति में एपस्टीन फाइल्स के जारी होने के बाद हंगामा मचा हुआ है। देश की नामी गिरामी हस्तियों के नाम इसमें सामने आए हैं। बिल क्लिंटन के बाद डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी इसमें नजर आया था। हालांकि, ट्रंप से जुड़ी एक तस्वीर को हटा दिया गया था लेकिन भारी विरोध के बाद अमेरिकी न्याय विभाग ने एक बार फिर से इन तस्वीरों को बहाल कर दिया है और इसके साथ ही तस्वीर हटाने की वजह भी बताई है। न्यूयॉर्क के सरकारी वकीलों ने पहले इस तस्वीर पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि इससे पीड़ितों की पहचान उजागर होने का खतरा हो सकता था। इसलिए एहतियात के तौर पर इस तस्वीर समेत कुल 16 फाइलों को कल वेबसाइट से हटा दिया गया था। जांच के बाद ऐसा कोई खतरा नहीं मिला, इसलिए फोटो को बिना किसी बदलाव के दोबारा जारी कर दिया गया। न्याय विभाग की तरफ से कहा गया कि न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ने पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा को देखते हुए इस तस्वीर को अस्थाई रूप से हटा दिया गया था। हालांकि, सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया के बाद इसे दोबारा अपलोड कर दिया गया। जारी की गई तस्वीर में एपस्टीन के किसी पीड़ित को साथ नहीं दिखाया गया है। एक तस्वीर में ट्रंप के साथ कुछ महिलाएं खड़ी दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर एक और तस्वीर में ट्रंप अपनी पत्नी मेलेनिया और जेफ्री एपस्टीन और उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई दे रही है।

न्याय विभाग ने क्या कहा- इस तस्वीर को जारी करने के साथ न्याय विभाग ने कहा, 'न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ने पीड़ितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की एक तस्वीर को संभावित आगे की कार्रवाई के लिए चिह्नित किया था। इसी समीक्षा के बाद विभाग ने उस तस्वीर को हटा दिया था, लेकिन फिर बाद में यह पाया गया कि इसमें एपस्टीन की कोई पीड़िता नहीं है, इसके बाद इसे जारी किया गया।

विपक्ष बोला- सरकार ट्रम्प को बचाने की कोशिश कर रही तस्वीर हटाने के बाद डेमोक्रेट नेताओं ने आरोप लगाए कि सरकार ट्रम्प को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश ने साफ कहा कि इसका ट्रम्प से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि पीड़ितों के अधिकारों से जुड़े समूहों ने फोटो हटाने को कहा था, ताकि सही जांच हो सके। जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा है कि वह पूरी पारदर्शिता रखता है और सिर्फ वही जानकारी हटाता है जो कानून के मुताबिक जरूरी हो। डिपार्टमेंट को पीड़ितों, नाबालिगों और संवेदनशील जानकारी की पहचान छिपानी होती है। ष्ठह्रछ्व ने यह भी साफ किया कि किसी बड़े या राजनीतिक व्यक्ति को बचाने के लिए कोई जानकारी नहीं हटाई जाएगी। डीओजे के पास कुछ ऐसे लोगों ने अपील दर्ज की है, जो खुद को पीड़ित बताते हैं और कुछ जानकारी हटाने की मांग करते हैं। ऐसे मामलों में कंटेंट को अस्थायी तौर पर हटाकर जांच की जाती है और जरूरत पड़ने पर सही बदलाव के साथ फिर जारी किया जाता है।

वकील बोलीं- पीड़ितों की पहचान सही तरीके से नहीं छिपाई गई- पीड़ितों की वकील ग्लोरिया ऑलरेड ने कहा कि कुछ दस्तावेजों में पीड़ितों के नाम और तस्वीरें ठीक से नहीं छिपाई गईं, जो गलत है। उन्होंने कहा कि इससे पीड़ितों को फिर से दुख पहुंचा है। एक पीड़िता ने यह भी कहा कि उसका नाम सार्वजनिक कर दिया गया, जबकि उसे अपनी ही फाइल देखने की इजाजत नहीं दी गई थी। उसने इसे अन्याय बताया। इस पूरे मामले को लेकर ट्रम्प प्रशासन की आलोचना हो रही है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

मतदाता सूची में नाम तो निश्चिंत ना हों, अब चुनाव आयोग करेगा असली जांच

-संतोषजनक तथ्य नहीं पेश कर पाने पर हटाए जा सकते हैं नाम

कोलकाता (एजेंसी)। सिर्फ इसलिए कि आपका नाम मसौदा मतदाता सूची में आ गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप निश्चिंत हो जाएं। अभी भी हो सकता है कि आपका नाम अंतिम मतदाता सूची से बाहर हो जाए। चुनाव आयोग की असली जांच अब शुरू होगी, जिन भी लोगों ने गणना प्रपत्र भरा है, उनमें से करीब सभी के नाम मसौदा सूची में हैं। इनमें करीब एक करोड़ 66 लाख नामों पर चुनाव आयोग को शक है। उन लोगों के तथ्यों की बारीकी से जांच की जाएगी।

जरुरत पड़ी तो उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। संतोषजनक तथ्य नहीं पेश कर पाने पर उनके नाम हटाए जा सकते हैं। किन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा, यह तय करने के लिए आयोग की अपनी पद्धति है।

मसौदा सूची में शामिल 30 लाख से ज्यादा मतदाताओं को सुनवाई का सामना करना होगा। बाकी एक करोड़ से ज्यादा मतदाताओं में से कुछ को जरुरत पड़ने पर सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।

30 लाख 59 हजार 273 मतदाता 2002 की सूची से अपना कोई लिंक नहीं दिखा पाए हैं यानी उनकी जानकारी 2002 से मैप नहीं हो पाई। इन सभी के नाम मसौदा सूची में हैं, हालांकि यह पक्का नहीं है कि वे वैध मतदाता हैं या नहीं इसलिए इन सभी को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।

नो मैपिंग कैटेगरी के मतदाताओं के अलावा आयोग को एक करोड़ 36 लाख और मतदाताओं पर शक है। आयोग को उनके गणना प्रपत्रों में मिली जानकारी संदिग्ध लग रही है इसलिए उन्हें वेरिफाई करने का फैसला किया गया है, हालांकि इन सभी को सुनवाई के लिए नहीं बुलाया जाएगा।

कुछ मामलों में मतदाताओं से उनके पिता या माता सिर्फ 15 साल बड़े हैं। कुछ मामलों में मतदाता अपने दादा या दादी से 40 साल भी छोटे नहीं हैं। कुछ मामलों में मतदाता और उसके माता-पिता के बीच उम्र का अंतर 50 साल से ज्यादा है।

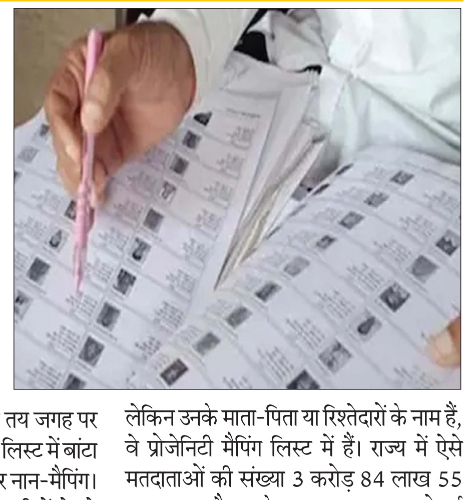

कुछ जगहों पर छह से ज्यादा मतदाताओं के पिता का नाम एक ही है। संबंधित इलाके के बीएलओ उन सभी के घर जाकर इसकी जांच करेंगे। जिनकी जानकारी से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। उन्हें बीएलओ घर-घर जाकर नोटिस देंगे। उन्हें यह भी बताया जाएगा कि उन्हें सुनवाई के लिए कब और कहां हाजिर होना है। इसी तरह संबंधित मतदाता को जरुरी दस्तावेजों के साथ तय दिन तय जगह पर पहुंचना होगा। मतदाताओं को तीन लिस्ट में बांटा है-अपनी मैपिंग, संतान मैपिंग और नान-मैपिंग। जिनके नाम 2002 की मतदाता सूची में थे, वे अपनी मैपिंग लिस्ट में हैं। ऐसे 2 करोड़ 93 लाख 69 हजार 188 मतदाताओं की पहचान की गई है, जिनके नाम 2002 की सूची में नहीं हैं, लेकिन उनके माता-पिता या रिश्तेदारों के नाम हैं, वे प्रोजेनिटी मैपिंग लिस्ट में हैं। राज्य में ऐसे मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 84 लाख 55 हजार 939 है। इसके अलावा 30 लाख वोटर्स ऐसे भी हैं, जिनके नाम या उनके रिश्तेदारों के नाम 2002 की सूची में नहीं हैं। वे नान-मैपिंग वोटर्स हैं। वे सभी इस तीसरी सूची में शामिल हैं।

दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री और पायलट में हुई हाथापाई, पायलट पर एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट द्वारा एक यात्री पर हमला करने के तीन दिन बाद, दिल्ली पुलिस को दोनों की शिकायतें मिलीं। पुलिस ने यात्री अंकित दीवान की शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। अंकित दीवान ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार को एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर ऑफ-ड्यूटी पायलट ने उन पर हमला किया। अंकित दीवान ने घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दीवान ने बताया कि विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने कुछ स्टाफ सदस्यों के सिक्योरिटी चेकपॉइंट पर लाइन तोड़ने पर चिंता जताई। इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पायलट को सस्पेंड कर दिया है। पहले बयान जारी करते हुए एयरलाइन ने कहा कि घटना के समय पायलट ऑफ-ड्यूटी था और एक यात्री के तौर पर यात्रा कर रहा था। बयान में यह भी कहा गया है कि यह पूरी तरह से दो यात्रियों के बीच का निजी मामला था और इसका उसके प्रोफेशनल रोल या एयरलाइन से कोई लेना-देना नहीं था। एयरलाइन ने कहा कि वह अगले हफ्ते घटना के सभी पहलुओं की जांच के लिए एक आंतरिक जांच करेगी। सूत्रों ने पहले बताया था कि घटना के बाद ऑफ-ड्यूटी पायलट बाद में बेंगलुरु के लिए इंडिगो की फ्लाइट में सवार हो गया था। कैप्टन सेजवाल ने अंकित दीवान पर बहस में जाति-आधारित टिप्पणी करने और उनके परिवार की महिला सदस्यों, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, को धमकी देने का आरोप लगाया है। सेजवाल के मुताबिक अंकित दीवान ने बिना किसी उकसावे के गाली-गलौज शुरू कर दी। यह टकराव हाथापाई में बदल गया।

चीनी वीजा घोटाला मामले में कार्ति चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की अदालत ने चीनी वीजा घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। यह मामला 2011 से जुड़ा है जब कार्ति के पिता पी. चिदम्बरम गृह मंत्रालय के मंत्री थे। पंजाब के तालवंडी साबो पावर लिमिटेड नाम की कंपनी की वॉर्डर के तहत 2011 में एक पावर प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसमें चीनी कर्मचारी काम कर रहे थे। इन लोगों के लिये स्पेशल प्रोजेक्ट वीजा जारी किये गए थे। कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने चीनी नागरिकों को भारत में काम करने के लिए वीजा दिलाने में अवैध तरीके से सहायता करने के एवज में रिश्वत ली और इससे जुड़े नियमों में अनियमितता कराई।

लखनऊ-वाराणसी हाईवे पर कोहरे के कारण टकराए कई वाहन, दो की मौत, 10 घायल

अमेठी (एजेंसी)। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर मंगलम स्कूल के पास कोहरे के चलते हुए हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 10 घायल हुए हैं। घने कोहरे के कारण कई वाहन आपस में टकरा गए। यह हादसा लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग अमेठी रोड ओबरब्रिज पर चार ट्रक, एक कार व बस घने कोहरे की वजह से आपस में टकरा गई। तीन हाइड्रा, चार जेसीबी रेस्क्यू के लिए लगाई गई हैं। हादसे के बाद मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ, एसडीएम, तहसीलदार पहुंच गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा रात ढाई बजे के करीब हुआ है। हादसे के बाद हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस हाईवे को जल्द यातायात सुचारु करने की कोशिश कर रहा है।

ओडिशा में 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया

भुवनेश्वर (एजेंसी)। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में मंगलवार को 22 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। इनमें एक संभागीय समिति सदस्य, छह एसीएम और 15 पार्टी सदस्य शामिल हैं। हर एक पर 5.5 लाख से लेकर 27.5 लाख तक का इनाम था। ओडिशा डीजीपी योगेश बहादुर खुराना ने बताया कि सभी नक्सलियों ने हथियारों के साथ सरेंडर किया है। मुझे उम्मीद है कि अन्य नक्सली भी सरेंडर करेंगे और मुख्यधारा में शामिल होंगे। गौरतलब है कि 31 मार्च तक देश को नक्सल मुक्त करने का अभियान चल रहा है। इस कारण नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है।

50 भारतीय अब भी रूसी सेना में, 26 की मौत

नई दिल्ली (एजेंसी)। रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में 202 भारतीयों ने रूसी सेना की तरफ से हिस्सा लिया, जिनमें से 119 को केंद्र सरकार के प्रयासों से वापस भारत लाया जा चुका है, वहीं 26 की मौत हो चुकी और सात लापता हैं। लगभग 50 भारतीय अब भी युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं। विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सांसद साकेत गोखले और रणदीपसिंह सुरजेवाला के सवालों के जवाब में बताया कि इन नागरिकों की शीघ्र रिहाई के लिए रूस के साथ लगातार कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। इस बीच गुजरात के युवक का वीडियो जारी हुआ, जिसमें बताया गया कि उसे ड्रग्स के मामले में झूठा फंसाकर रूसी सेना में शामिल कर लिया है।

गुरुग्राम में एक फार्म हाउस पर हुई छापेमारी...कुल 18 गिरफ्तारियां, जिसमें 16 विदेशी नागरिक

गुरग्राम (एजेंसी)। हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम में नए साल के जश्न से पहले पुलिस पूरी मुस्तैदी में दिख रही है। भोंडसी स्थित एक फार्म हाउस पर हुई छापेमारी ने अवैध गतिविधियों के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। छापेमारी का विवरण एलिगेंट फार्म बी-2, बहलपा ग्रीन, भोंडसी (गुड़गांव)। छापेमारी में कुल 18 गिरफ्तारियां, जिनमें 16 विदेशी नागरिक (नाइजीरियाई) शामिल हैं। इनमें तीन युवतियां और एक महिला भी है। पुलिस ने 3 लाख 20 हजार रुपये कैश (जुआ खेलने के लिए इस्तेमाल) बरामद किया। जबकि करीब 5 लाख रुपये की शराब (24 पेटी महंगी शराब और 16 पेटी बियर) पकड़ी। पुलिस ने आरोपियों पर कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। अवैध रूप से शराब परोसने और पीने के लिए, फार्म हाउस में जुआ खिलाने और खेलने के लिए केस दर्ज हुआ है। पकड़े गए विदेशी नागरिक अपने पासपोर्ट और वीजा के दस्तावेज नहीं दिखा पाए। पुलिस संबंधित एंबेसी (दूतावास) को सूचित कर रही है और इन सभी विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट (देश निकाला) करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

गंगा लिंक एक्सप्रेसवे को मिली रफ्तार, निर्माण के लिए 1246 करोड़ रुपये का प्रावधान

नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट में नोएडा और आस-पास के क्षेत्रों के विकास को बड़ी सौगात दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड गंगा लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, जिसके लिए 1246 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास और बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार गंगा एक्सप्रेसवे को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए 74 किलोमीटर लंबे नए लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगी। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बुलंदशहर के स्याना से शुरू होकर यमुना सिटी में फिल्म सिटी के पास यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इस 74 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे का करीब 21 किलोमीटर हिस्सा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यमुना अथॉरिटी) क्षेत्र में आएगा। इसमें से लगभग 9 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के रूप में बनाया जाएगा। इसके अलावा यमुना सिटी के सेक्टर क्षेत्र में 24 मीटर चौड़ी सर्विस रोड का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे स्थानीय आवागमन को सुविधा मिलेगी। यमुना अथॉरिटी अपने क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू करेगी। इसके तहत 16 गांवों की करीब 740 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। जमीन अधिग्रहण के बाद एक्सप्रेसवे निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। अनुपूरक बजट में नोएडा के हेल्थ सेक्टर को भी प्राथमिकता दी गई है। चाइल्ड पीजीआई नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए भी बजट आवंटित किया गया है, जिससे क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। गंगा लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यमुना सिटी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे न केवल औद्योगिक और निवेश गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

मनरेगा के मूल उद्देश्य को कमजोर कर रहा केंद्र, किसान मजदूर संघर्ष समिति ने लगाए आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी)। किसान मजदूर संघर्ष समिति (केएमएससी) के नेता सतनाम सिंह पन्नू ने मंगलवार को आरोप लगाया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को कमजोर किया जा रहा है और ग्रामीण एवं श्रमिक वर्ग के परिवारों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने मूल उद्देश्य से भटकाया जा रहा है। पन्नू ने कहा कि 2005 में शुरू होने के बाद से एमजीएनआरईजीए एक अधिकार-आधारित कार्यक्रम के रूप में कार्य करता रहा है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा किए गए हालिया परिवर्तनों ने इसकी संरचना को बदल दिया है। उन्होंने देश भर में जारी किए गए 26 करोड़ जॉब कार्डों के आधिकारिक आंकड़ों का हवाला दिया, जिनमें से 12 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिला है। पंजाब में 20 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें से 11 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला है।

पन्नू ने कहा कि देश भर में इस योजना के तहत लगभग 26 करोड़ जॉब कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें से लगभग 12 करोड़ लाभार्थियों को रोजगार मिला है। अकेले पंजाब में ही लगभग 20 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए हैं और लगभग 11 लाख श्रमिकों को एमजीएनआरईजीए के तहत काम मिल रहा है। हालांकि, यह आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने एमजीएनआरईजीए की संरचना में मौलिक रूप से बदलाव किया है और इसे एक नए रूप में पेश किया है, जिससे इसके मूल उद्देश्यों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने दावा किया कि ÷केंद्र सरकार ने ग्राम सभाओं और पंचायतों की शक्तियां छीन ली हैं, जो पहले गांवों में विकास कार्यों का निर्णय करती थीं।

बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने में जुटी महबूबा

-हिजाब से जोड़कर आपत्तिजनक बयान दिया

जम्मू (एजेंसी)। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न पर चिंता जताने के नाम पर पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह भारत के लोकतांत्रिक ताने-बाने और कानून-व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया हैं वहां आपत्तिजनक है। सबसे पहले सच्चाई यहां हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कोई खोखला नारा नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व है। किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ अपराध होता है, तब उसके लिए कानूनी प्रक्रिया मौजूद है, एफआईआर से लेकर न्यायालय तक सबकुछ देश में मौजूद है। छिटपुट घटनाओं को लेकर पूरे देश को 'नैतिक दुविधा' में बताना, दरअसल भारत की संस्थाओं और लोकतंत्र पर सीधा हमला है।

इसके उलट महबूबा का यह कहना कि भारत का नेतृत्व 'नैतिक दुविधा' में है, दरअसल राजनीतिक एजेंडे की बू देता है। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के सिंदूर लगाने तक से डरने की खबरें आई हैं, इसके बाद अपेक्षा थी कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर रह चुकीं महबूबा मुफ्ती कड़े शब्दों में बर्बरता की निंदा करेंगी और पीड़ितों के साथ खड़ी होंगी। लेकिन महबूबा ने राजनैतिक रोटियां सेंकते हुए भारत के भीतर हिजाब से जुड़ी बहस से जोड़ दिया। यह तुलना न सिर्फ असंगत है, बल्कि एक तरह से बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को तर्कों की आड़ में जायज ठहराने जैसा प्रतीत होती है। महबूबा को याद रखना चाहिए कि भारत में हिजाब या किसी भी धार्मिक प्रतीक को लेकर बहसें न्यायालयों और संवैधानिक दायरे में होती हैं। यहां कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई होती है, चाहे वे किसी भी धर्म से हों। इसके विपरीत, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक महिलाओं को उनकी पहचान के कारण डर में जीने पर मजबूर किया जा रहा है। दोनों स्थितियों को एक ही तराजू पर तौलना गलत है।

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, बांग्लादेश से आ रही खबरें बहुत परेशान करने वाली हैं, जिसमें कहा गया है कि हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाकर बाहर निकलने से डरती हैं।'' महबूबा ने कहा कि अपने देश का नेतृत्व नैतिक दुविधा में है क्योंकि यहां ''अराजक तत्व मुस्लिम महिलाओं का हिजाब जबरदस्ती उतार रहे हैं। उन्होंने कहा, ''दुख की बात है कि भारतीय नेतृत्व को बांग्लादेशी अधिकारियों के सामने गंभीर मुद्दे को उठाने में एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देश में ही कुछ अराजक तत्व मुस्लिम महिलाओं के हिजाब जबरदस्ती उतारते देखे जा रहे हैं। कट्टरपंथियों से भरी इस दुनिया में महिलाओं के अधिकारों और गरिमा के लिए वास्तव में कौन खड़ा होगा?

राज्यसभा में और घटेगी विपक्ष की ताकत, 75 सीटों पर चुनाव, अधिकांश में एनडीए

नई दिल्ली (एजेंसी)। नए वर्ष में राज्यसभा की 75 सीटें रिक्त हो रही हैं। जिन पर चुनाव के बाद जहां सत्ता पक्ष की ताकत बढ़ेगी, वहीं विपक्ष की ताकत और घट जाएगी। वर्तमान में राज्यसभा में एनडीए की 129 सीटें हैं, जबकि विपक्षी दलों के 78 सांसद हैं। हाल ही में बिहार सहित अन्य राज्यों में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद हो रहे चुनाव में अधिकांश सीटों पर एनडीए की जीत लगभग तय है। इससे लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी एनडीए ताकतवर बनकर उभरेगी। अगले वर्ष बिहार, उत्तरप्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के साथ कई पूर्वोत्तर के राज्यों की सीटें भी खाली होने वाली हैं। इनमें से कई राज्यों में एनडीए का पलड़ा भारी है।

इनका कार्यकाल खत्म- अगले वर्ष 2026 में जिन दिग्गज नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, दिग्विजय सिंह, शरद पवार और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन शामिल हैं।

सरकार मनरेगा का नाम बदलकर नए प्रयोगों से गरीबों का हक कम कर रही: सचिन पायलट

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने मनरेगा का नाम बदलने का विरोध किया और कहा कि नया विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी ग्रामीण रोज़गार योजना को खत्म कर देगा। पायलट ने तर्क दिया कि नई योजना ग्रामीण रोजगार के अधिकार मनरेगा को कमजोर कर सकती है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार मनरेगा जैसे स्थापित ढांचे के बजाय नए प्रयोगों से गरीबों का हक कम कर रही है।

कांग्रेस महासचिव पायलट ने केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार कानून 'मनरेगा' का नाम बदले जाने को 'ऐतिहासिक गलती' और 'सबसे वंचित लोगों' की आजीविका के अवसरों पर एक सुनियोजित हमला करार दिया है। उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं-सोनिया गांधी और राहुल गांधी को झूठा फंसाकर लगातार 'राजनीतिक प्रतिशोध' लेने का भी आरोप लगाया।

पायलट ने कहा कि भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक गलती की है। आजादी के बाद इतिहास में पहली बार राष्ट्रपिता के नाम पर शुरू की गई किसी योजना या कार्यक्रम का नाम बदला गया है। भारत में ग्रामीण भारत की वित्तीय सुरक्षा के लिए मनरेगा नामक जो एकमात्र नेटवर्क था उसे सरकार ने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को राज्य सरकारों, हितधारकों और नागरिक संस्था से बिना किसी चर्चा के रद्द कर दिया गया है और संसद का इस्तेमाल 'बहुमत की ताकत' दिखाने और कानून को जबरदस्ती पारित कराने के लिए किया गया।

बीजेपी पर 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में फंसाकर 'राजनीतिक प्रतिशोध' लेने का आरोप लगाते हुए पायलट ने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि वह ईडी द्वारा दायर मामले का संज्ञान नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश से यह स्पष्ट हो जाता है कि मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित था...हम निर्दोष साबित हुए हैं।

इसके अलावा कांग्रेस की कर्नाटक यूनिट में पावर स्ट्रगल की अटकलों को कम करते हुए पायलट ने कहा कि सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार पूरी तालमेल से काम कर रहे हैं और पार्टी हाई कमान द्वारा लिया गया कोई भी फैसला सभी को मंजूर होगा। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए जब डिप्टी सीएम शिवकुमार उनके बगल में बैठे थे, तो पायलट ने अंदरूनी कलह की बातों को खारिज कर दिया। पायलट ने कहा कि जब राज्य कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार ने सीएम सिद्धारमैया को अपना बड़ा भाई कहा है और सीएम कहते हैं कि वह शिवकुमार मेरे छोटे भाई हैं, तो बात वहीं खत्म हो जाती है।

ममता का आरोप बोली- भाजपा बंगाल के डेढ़ करोड़ मतदाताओं को वोट से वंचित करना चाहती है

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा डेढ़ करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश कर रही है, जो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने जैसा है। उन्होंने दावा किया कि बर्दवान में बाहर के राज्यों, खासकर बिहार से मोटरसाइकिलें लाई जा रही हैं और चुनाव के लिए बाहरी लोगों को लाने की कोशिश हो रही है। ममता ने कहा कि एसआईआर को लेकर सभी बीएलए को स्थानीय विधायक, पार्षद और ब्लॉक अध्यक्षों से सलाह करनी चाहिए।

बनर्जी ने कोलकाता में आयोजित पार्टी बैठक में कहा कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र संस्था की तरह काम नहीं कर रहा, बल्कि भाजपा के निर्देशों पर चल रहा है। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची तैयार करने में भारी स्तर पर गलतियां हुई हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो पार्षद और पार्टी कार्यकर्ता निष्क्रिय रहेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बूथ स्तर के एजेंटों को सतर्क रहने और मतदाताओं की रक्षा करने का निर्देश दिया। ममता ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया जानबूझकर की जा रही है ताकि खास समुदायों के वोट छीने जा सकें।

ममता बनर्जी ने एसआईआर को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए प्रशासनिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। ममता ने केंद्र से भेजे गए माइक्रो ऑब्जर्वरों की नियुक्ति पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों को स्थानीय भाषा और हालात की समझ नहीं है, जिससे आम मतदाताओं को परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वह बिना बंगाल सरकार को जानकारी दिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर रही है और भाजपा के हित साध रही है। उन्होंने कहा कि केवल टीएमसी के कार्यकर्ता ही राज्य में भाजपा की पैठ रोक सकते हैं।

2025 में पीएम मोदी ने की 23 देशों की 11 विदेश यात्राएं, कोविड के बाद सर्वाधिक दौरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की अपनी चार दिवसीय महत्वपूर्ण विदेश यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौटे हैं। इस यात्रा का सबसे प्रमुख पहलू ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर करना रहा। यह दौरा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अहम था, बल्कि इसने चालू वर्ष 2025 को प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के लिहाज से एक ऐतिहासिक साल बना दिया है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष प्रधानमंत्री ने कुल 11 विदेश यात्राएं कीं, जिनके माध्यम से उन्होंने 23 देशों का दौरा किया और लगभग 42 दिन विदेशी धरती पर व्यतीत किए।

वर्ष 2015 के बाद यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री की वैश्विक सक्रियता इस स्तर पर देखी गई है। अगर पिछले रिकॉर्ड्स पर नजर डालें, तो 2015 में उन्होंने 13 यात्राओं के दौरान 28 देशों का दौरा किया था और 54 दिन विदेश में बिताए थे। उस वर्ष के बाद, 2025 उनके कार्यकाल का सबसे सक्रिय और व्यापक विदेश दौरों वाला वर्ष साबित हुआ है। इस साल की विदेश नीति में एक स्पष्ट रणनीतिक बदलाव भी देखने को मिला है। मई माह के बाद, विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत, इन दौरों की आवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

इन यात्राओं के पीछे ठोस आर्थिक और रणनीतिक कारण निहित रहे हैं। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, जब चीन ने दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, भारत के लिए इनके वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करना अनिवार्य हो गया था। प्रधानमंत्री के दौरों का एक बड़ा लक्ष्य इन संसाधनों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना रहा। इसके साथ ही, अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने के बाद, भारत को अपने निर्यात बाजार में विविधता लाने की तत्काल आवश्यकता थी। ओमान और अन्य अफ्रीकी व मध्य-पूर्वी देशों के साथ हुए समझौते इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं, ताकि भारतीय उत्पादों के लिए नए और सुरक्षित बाजार तैयार किए जा सकें।

प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में आई इस तेजी का एक अन्य कारण घरेलू राजनीतिक कैलेंडर भी रहा। वर्ष 2024 की तुलना में, जब लोकसभा चुनावों के साथ-साथ कई बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, वर्ष 2025 में चुनावी व्यस्तताएं अपेक्षाकृत कम रहीं। केवल दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में चुनाव होने के कारण प्रधानमंत्री को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिए अधिक समय मिल सका। तुलनात्मक रूप से देखें तो उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में कोविड-19 महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय यात्राएं लगभग थम सी गई थीं। वर्ष 2020 में जहां कोई यात्रा नहीं हुई, वहीं 2021 और 2022 में भी वैश्विक प्रोटोकॉल के चलते सक्रियता सीमित रही। अब, सामान्य होते हालातों और बदलती वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के बीच, ये हालिया दौरे भारत को एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की कोशिश के रूप में देखे जा रहे हैं।